सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 197, नई दिल्ली । गुरुवार, 26 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 DUSU चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
06 संचार के जाल में में उलझा बचपन
08 आधुनिक युग में लॉजिस्टिक्स उद्योग का इतिहास और इसकी महत्ता

परिवहन विभाग द्वारा जारी हुए वाहन जांच केंद्र की समय सारिणी और स्टाफ के नाम

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा आज एक आदेश जारी कर दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों की जांच केंद्र (झूलझूली और बुराड़ी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम जारी किए। इस आदेश के अनुसार अब झूलझूली में दो शिफ्टो में वाहन जांच होंगी लेकिन शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे की है इस के बारे में इस आदेश मे नही बताया गया। इसी आदेश के अनुसार बुराड़ी वाहन जांच केंद्र में कार्य एक शिफ्ट में ही रहेगा पर समय उसका भी नही बताया गया। *सबसे महत्वपूर्ण बात जो व्यवसायिक वाहन मालिकों के जानने के लिए जरूरी है उनका विवरण इस आदेश मे नही दिया गया।

यहां यह बताना जरूरी था की

1. झुलझुली केंद्र में शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक कार्य करेगी

2. झूलझूली केंद्र में पहुंचने वाले वाहन मालिकों और वाहनों की सुरक्षा के प्रति विभाग द्वारा क्या किया गया है?

3. बुराड़ी केंद्र में वाहन जांच कितने बजे से कितने बजे तक कार्य करेगी

4. बुराड़ी केंद्र में किस श्रेणी के वाहनों की जांच होगी और झूलझूली केंद्र में किस श्रेणी के वाहनों की जांच होगी।

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी जानते हैं की झूलझूली वाहन जांच केंद्र पर जाने वाले वाहनों और उनके मालिकों को वहा सुरक्षा मुहैया करवाना अनिवार्य है क्योंकि पहले भी ना सिर्फ वाहन मालिकों के साथ अपितु अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी पर भी वहा मारा मारी हो चुकी हैं जिसकी बकायदा पुलीस एफआईआर भी दर्ज है और कई वाहनों के वहा से गायब/ चोरी होने की भी शिकायते और एफआईआर दर्ज है **ऐसे हालातों के होते हुए भी आला अधिकारी का एक पक्षीय निर्णय व्यवसायिक वाहन मालिकों के गले से नीचे नही उतर रहा पर रोजी रोटी के लिए मरना पड़ा तो भी उनकी मजबूरी है क्योंकि परिवार का भरण पोषण तो बाप/ पिता का पहला फर्ज है पर आला पद पर कार्यरत अधिकारी को इससे क्या लेना देना जव दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन के प्रमुख उपराज्यपाल भी उनके साथ है ना की जनता की सुरक्षा के साथ।**

इसी आदेश के अनुसार मॉल रोड परिवहन क्षेत्रीय शाखा के डीटीओ को वजीरपुर क्षेत्रीय शाखा के डीटीओ का चार्ज दे दिया गया है। आपकी जानकारी हेतु बता दें रोहिणी शाखा का चार्ज पहले से ही दिया हुआ था और अब वजीरपुर शाखा का चार्ज भी दे दिया है। **कुल मिलाकर परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा बिना किसी घोषणा को किए तीनो शाखाओं का काम एक शाखा के सुपूर्द कर दिया।**

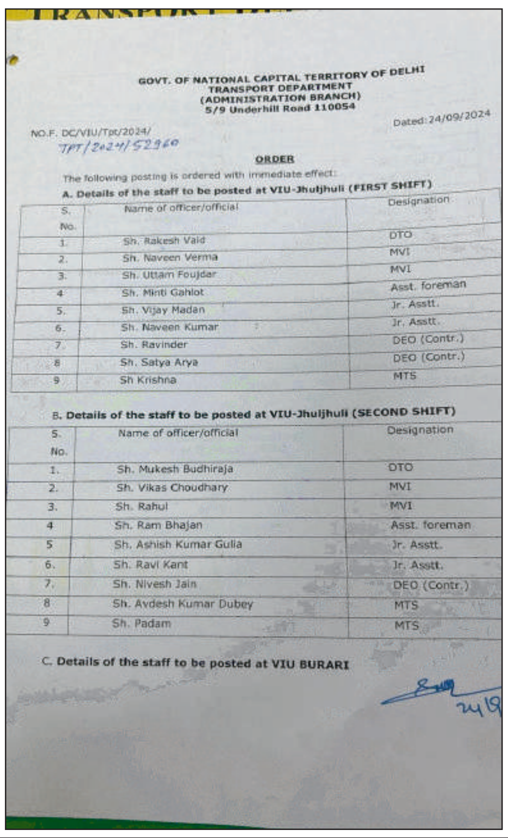

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
(ADMINISTRATION BRANCH)
5/9 Underhill Road 110054

NO.F. DC/VIU/Tpt/2024/ TPT/2024/52960 Dated: 24/09/2024

ORDER

The following posting is ordered with immediate effect:

A. Details of the staff to be posted at VIU-Jhuljhuli (FIRST SHIFT)

S. No.	Name of officer/official	Designation
1.	Sh. Rakesh Vaid	DTO
2.	Sh. Naveen Verma	MVI
3.	Sh. Uttam Foujdar	MVI
4	Sh. Minti Gahlot	Asst. foreman
5.	Sh. Vijay Madan	Jr. Asstt.
6.	Sh. Naveen Kumar	Jr. Asstt.
7.	Sh. Ravinder	DEO (Contr.)
8	Sh. Satya Arya	DEO (Contr.)
9	Sh Krishna	MTS

B. Details of the staff to be posted at VIU-Jhuljhuli (SECOND SHIFT)

S. No.	Name of officer/official	Designation
1.	Sh. Mukesh Budhiraja	DTO
2.	Sh. Vikas Choudhary	MVI
3.	Sh. Rahul	MVI
4	Sh. Ram Bhajan	Asst. foreman
5	Sh. Ashish Kumar Gulia	Jr. Asstt.
6.	Sh. Ravi Kant	Jr. Asstt.
7.	Sh. Nivesh Jain	DEO (Contr.)
8	Sh. Avdesh Kumar Dubey	MTS
9	Sh. Padam	MTS

C. Details of the staff to be posted at VIU BURARI

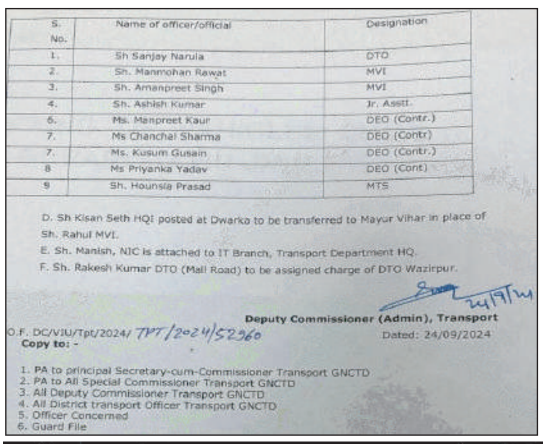

S. No.	Name of officer/official	Designation
1.	Sh Sanjay Narula	DTO
2.	Sh. Manmohan Rawat	MVI
3.	Sh. Amanpreet Singh	MVI
4.	Sh. Ashish Kumar	Jr. Asstt.
6.	Ms. Manpreet Kaur	DEO (Contr.)
7.	Ms Chanchal Sharma	DEO (Contr)
7.	Ms. Kusum Gusain	DEO (Contr.)
8	Ms Priyanka Yadav	DEO (Cont)
9	Sh. Hounsla Prasad	MTS

D. Sh Kisan Seth HQI posted at Dwarka to be transferred to Mayur Vihar in place of Sh. Rahul MVI.
E. Sh. Manish, NIC is attached to IT Branch, Transport Department HQ.
F. Sh. Rakesh Kumar DTO (Mall Road) to be assigned charge of DTO Wazirpur.

Deputy Commissioner (Admin), Transport

O.F. DC/VIU/Tpt/2024/ TPT/2024/52960 Dated: 24/09/2024

Copy to: -

1. PA to principal Secretary-cum-Commissioner Transport GNCTD
2. PA to All Special Commissioner Transport GNCTD
3. All Deputy Commissioner Transport GNCTD
4. All District transport Officer Transport GNCTD
5. Officer Concerned
6. Guard File

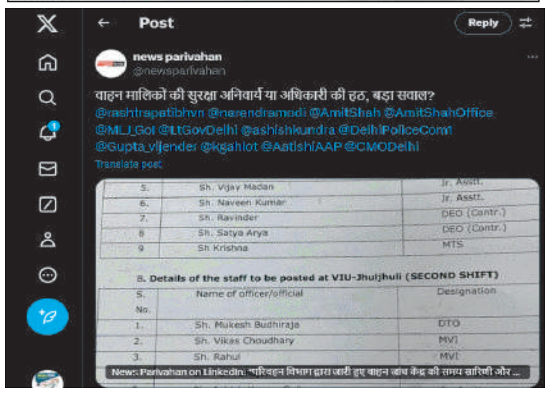

संपादक के नाम पत्र

रोहिणी क्षेत्र के निवासी की दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी और प्रशासन से सुरक्षा के प्रति निवेदन

प्रिय संपादक साहब,

मुझे आपके पेपर की ई-कॉपी प्राप्त हुई है, जो दिल्ली में परिवहन प्रबंधन के लिए विशेष है। बहुत अच्छी पहल है। मैं पेपर के लिए और अधिक सफलता की कामना करता हूँ। आपके पेपर के माध्यम से, मैं परिवहन प्राधिकरण का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि रोहिणी क्षेत्र में बिना किसी रोक-टोक के, बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चल रहे हैं और मेट्रो स्टेशन के आसपास पैदल चलने के लिए जगह घेर रहे हैं। वे अपने वाहनों की हेडलाइट और टेल लाइट जलाने की भी परवाह नहीं करते हैं। उनकी गति बहुत तेज है। मैं प्राधिकारियों से अपील करता हूं कि वे इन्हें ले जाएं तथा केवल अधिकृत ई-रिक्शा को ही अनुमति दें, कभी-कभी वाहनों से पाइप और व्यावसायिक सामग्री बाहर निकलती हुई देखी जाती है।

धन्यवाद

श्री गोपाल कैस्था
(SRI GOPAL KAISTHA)
रोहिणी.

सड़क से जुड़े सर्व समाज एवं वाहन चालकों के हित में लिया गया फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 22-9-2024 को श्री भूपिंदर सिंह किरार के नेतृत्व में कार्यालय में सड़क से जुड़े सर्व समाज एवं सभी यूनियन अध्यक्षों और मार्शल गार्ड, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई । दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष सरदार बख्शी सिंह, अध्यक्ष, माननीय स॰ तजिंदर सिंह ऑर्गेनाइजेशन सैक्रेटरी और माननीय नेम सिंह चौहान, निदेशक (सशक्त भारतीय मानवाधिकार संघ) शामिल थे, केन्द्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में सहकारिता विभाग के अध्यक्ष माननीय अशोक ठाकुर, अध्यक्ष, सहकारिता विभाग और एमसीडी अध्यक्ष शाहदरा संदीप कपूर शामिल थे। जिसमें शाहदरा के नगर निगम पार्षद माननीय संदीप कपूर को जिम्मेदारी दी गई , चर्चा का विषय था सड़क से जुड़े समाज और होटल, ठेकेदारों की समस्या।

इसके चलते नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों, परिवारों से भटकते लोगों और सरकार से मदद न मिलने के कारण कई परिवारों से जुड़े सदस्यों की हुई असामयिक मौतों पर गहन चर्चा हुई.

चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की एक टीम जल्द गठित की जाएगी, टीम को पर्यटन, होटल, श्रमिक, सड़क से जुड़े अन्य समाज और ड्राइवरों के अधिकारों के लिए भाजपा की केंद्र सरकार से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

दिल्ली में अभी लागू रहेगी पुरानी ईवी पॉलिसी, मिलेगी सब्सिडी

जो इलैक्ट्रिक वाहन मालिक पंजीकरण फीस और टैक्स जमा कराकर पंजीकरण करवा रहे हैं और जो टैक्स जुर्माने के साथ भर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा मंत्री परिवहन दिल्ली सरकार द्वारा, इस विषय पर भी जनता को जवाब देना तो बनता है : संजय बाटला

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। यहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रुके हुए कामों को गति देने की बात कर रहे हैं।

इस बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ईवी पॉलिसी 2.0 तैयार करने में करीब डेढ़ महीने का समय लगेगा, लेकिन उससे पहले पुरानी ईवी पॉलिसी को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। इस पर काम चल रहा है। साथ ही जिन लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिली है, उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी।

दिल्ली में 07 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त 2024 तक कुल 3,16,334 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। दिल्ली सरकार खुद करीब 2 हजार इलेक्ट्रिक बसें चला रही है।

दिल्ली सरकार ने अब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को 179 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। जनवरी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। परिवहन विभाग से रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर अनिल छिक्कारा ने बताया कि उन्होंने भी इस साल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, लेकिन उन्हें अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है। सब्सिडी न मिलने से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों का मनोबल टूटेगा। साथ ही दिल्ली में जगह-जगह लगे चार्जिंग स्टेशन खराब हो रहे हैं। ऐसे में जब लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेकर घर से निकलते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि रास्ते में चार्जिंग की सुविधा न मिलने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में जगह-जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए कई निजी संस्थाओं ने चार्जिंग प्वाइंट बनाए हैं। इन चार्जिंग प्वाइंट को बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन सब्सिडी न मिलने से चार्जिंग पॉइंट के संचालक भी परेशान हैं। हालात ये हैं कि जगह-जगह लगाए गए चार्जिंग पॉइंट महज शोपीस बनकर रह गए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि दिल्ली में कुल 4,793 चार्जिंग प्वाइंट, 31,000 चार्जिंग स्टेशन और 318 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

दिल्ली में पुरानी ईवी पॉलिसी खत्म हो गई है। पहले इस ईवी पॉलिसी को दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। दूसरी बार इस पॉलिसी को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया। अभी नई ईवी पॉलिसी नहीं आई है। दिल्ली सरकार महीनों से नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक ईवी पॉलिसी 2.0 लागू नहीं हो पाई है। मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि नई ईवी पॉलिसी बनाने में करीब डेढ़ महीने का समय लगेगा, तब तक पुरानी ईवी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने प्रस्ताव लाया जाएगा। इस दौरान जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे और उन्हें सब्सिडी नहीं मिली, उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

एलजी ने मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, दिया एक अनोखा आइडिया; पढ़ें- कैसे सड़क हादसों में आएगी कमी

दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ट्रैफिक जुर्माने की संख्या को वाहनों के बीमा प्रीमियम से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। जानिए इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से।

नई दिल्ली। राजधानी में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ट्रैफिक जुर्माने की संख्या को वाहनों के बीमा प्रीमियम से जोड़ने की मांग की है।

एलजी ने अपने पत्र में लिखा कि किसी भी वाहन की बीमा प्रीमियम की राशि को उस वाहन के खिलाफ दर्ज यातायात नियमों के उल्लंघनों की संख्या से जोड़ने से सड़क हादसों में कमी आएगी। साथ ही बीमा प्रीमियम की लागत बढ़ेगी और आर्थिक नुकसान के डर से लोग स्वतः ही यातायात नियमों का उल्लंघन करना कम कर देंगे। इससे हर साल होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।

एलजी ने आगे पत्र में लिखा है कि इसी तरह के उपायों को अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। साथ ही अपनी सलाह के समर्थन में उन्होंने सड़क हादसों को लेकर विश्व बैंक और दिल्ली पुलिस के विश्लेषण का भी जिक्र किया।

2022 में 4.37 लाख ज्यादा दुर्घनाएं दर्ज की गई

उन्होंने लिखा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत में सन् 2022 में 4.37 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें लगभग 1.55 लाख लोगों की मौत हुई। इन दुर्घटनाओं में करीब 70 प्रतिशत हादसे ओवर-स्पीडिंग यानी तेज गति में वाहन चलाने की वजह से हुए। साथ ही रेड-लाइट जंपिंग जैसे उल्लंघन ने भी घातक दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

आगे उन्होंने विश्व बैंक द्वारा किए गए दुर्घटना के आंकड़ों के विश्लेषण का जिक्र करते हुए बताया कि यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहनों के घातक दुर्घटनाओं में शामिल होने की आशंका साफ ड्राइविंग रिकार्ड वाले वाहनों की तुलना में 40 फीसदी तक ज्यादा रहती है।

दिल्ली में 60 प्रतिशत चालान कटे वाहन दुर्घटनाओं में रहते शामिल

एलजी ने पत्र में दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को भी उजागर किया है। ट्रैफिक पुलिस की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत भीषण सड़क दुर्घटनाएं उन वाहनों से हुई हैं, जिन पर पहले से ही यातायात उल्लंघन, मुख्य रूप से ओवर स्पीडिंग और रेड-लाइट जंपिंग के लिए जुर्माना किया जा चुका था।

हादसों में कमी आएगी, कंपनियों का बोझ कम होगा

एलजी ने इसके फायदे बताते हुए लिखा, "बीमा प्रीमियम को यातायात उल्लंघनों से जोड़ने से न केवल बीमा लागत जोखिम के साथ एकरूप होगी, बल्कि लगातार दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों के कारण बीमा कंपनियों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। यह बाजार-संचालित निदान जिम्मेदार ड्राइविंग को प्रोत्साहित करेगा। दुर्घटनाओं को कम करने, जीवन बचाने और बीमा दावों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने में योगदान देगा।"

पाकिस्तान के शिव मंदिर में 3,000 साल से भी पुराना शिवलिंग, जानिए मंदिर का महत्व

अनन्या मिश्रा

इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को अपने पूजा स्थलों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि कुछ वर्षों बाद इन दो फेमस शिव मंदिरों का फिर से पुर्नजीवित किया गया।

वैसे तो हमारे देश में भगवान शिव को समर्पित तमाम मंदिर हैं। यह मंदिर बेहद प्राचीन हैं और इनकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी शिव मंदिर हैं। जहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल 1947 में जब देश का बटवारा हुआ तो अटारी और वाघा के बीच एक रेखा खींची गई।

विभाजन की इस रेखा से न सिर्फ हजारों-लाखों लोगों के घर, जमीन और खेत उजड़े बल्कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को अपने पूजा स्थलों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि कुछ वर्षों बाद इन दो शिव मंदिरों का फिर से पुर्नजीवित किया गया। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पाकिस्तान में स्थित दो फेमस शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं।

चिट्टी-गट्टी शिवलिंग मंदिर

मनसेहरा से करीब 10 किमी की दूरी पर काराकोरम राजमार्ग पर स्थित चिट्टी गट्टी मंदिर है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यह शिव मंदिर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। साल 1948 में पाकिस्तान के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को सीलकर आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया था। साल 1998 तक यह क्षेत्र की छोटी हिंदू आबादी के लिए बेहद दुर्गम बना रहा। फिर हिंदुओं ने अपनी आस्था और विरासत के लिए फिर से इस मंदिर में पूजा-अर्चना करना शुरूकर दिया।

3,000 साल से भी पुराना शिवलिंग

पाकिस्तान का अब सबसे लोकप्रिय मंदिरों में शामिल चिट्टी-गट्टी शिवलिंग मंदिर है। यह पाकिस्तान से तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासकर महाशिवरात्रि के मौके पर यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। पाकिस्तानी हिंदुओं द्वारा इस मंदिर की पुनर्स्थापना बड़े पैमाने पर की गई थी। जिन्होंने न सिर्फ श्रम बल्कि धन से भी योगदान किया। बताया जाता है कि इस मंदिर में 3000 साल पुरानी शिवलिंग है। यह पाकिस्तान का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है।

कटास राज मंदिर

बता दें कि पंजाब के चकवाल जिले में भव्य कटास राज शिव मंदिर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण और फेमस पवित्र हिंदू स्थलों में से एक है। कटास राज में वास्तव में सात मंदिर शामिल हैं। जो वर्तमान समय में सिर्फ तीन ही बचे हैं। जो मंदिर तालाब की परिधि के आसपास बने हैं और यह करीब 900 साल पुराना माना जाता है। इतिहासकारों एवं पुरात्तव विभाग के मुताबिक इस स्थान को शिव नेत्र माना जाता है।

मंदिर से जुड़ी मान्यता

मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती की मृत्यु पर दो आंसू बहाए थे, तब इस तालाब का निर्माण हुआ था। बताया जाता है कि भगवान शिव की आंसू की एक बूंद से कटासराज में तालाब बन गया। तो वहीं दूसरा बूंद अजमेर के पुष्कर में गिरा था। उत्तरी पंजाब से हिंदुओं के चले जाने से कटासराज एक खंडहर में बदल गया और इस तालाब में कचरा भर गया। फिर साल 1982 में हिंदुओं ने मंदिर की पुर्नस्थापना की।

अन्य देशों में शिव मंदिर

भगवान शिव एक हिंदू देवता हैं। भगवान शिव की पूजा लोग अज्ञान विनाशक के रूप में भी करते हैं। हिंदू धर्म में तीन मुख्य देवताओं में से एक के रूप में उनकी पूजा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। भारत के अलावा भी अन्य देशों में शिव मंदिर हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के अलावा अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फेमस शिव मंदिर हैं।

मध्य प्रदेश की इन शानदार जगह को मानसून में जरूर करें एक्सप्लोर, देखने को मिलेंगे व्हाइट टाइगर

मध्य प्रदेश में स्थित रीवा एक ऐसी जगह है, जो मानसून में सैलानियों को खूब आकर्षित करती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रीवा की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह देश के मध्य में होने से इसको हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर ऐसी कई ऐतिहासिक और अद्भुत जगहें मौजूद हैं, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। मध्य प्रदेश में स्थित रीवा एक ऐसी जगह है, जो मानसून में सैलानियों को खूब आकर्षित करती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रीवा की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको मानसून में जरूर जाना चाहिए।

पुरवा वॉटरफॉल

मध्य प्रदेश के रीवा में आप पुरवा वॉटरफॉल घूमने जा सकते हैं। यह घूमने के लिहाज बेहद शानदार और अद्भुत जगह है। मानसून के समय यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी मस्ती करने के लिए पुरवा वॉटरफॉल पहुंचते हैं।

पुरवा वॉटरफॉल में जब 230 फीट की ऊंचाई से पानी जमीन पर गिरता है, तो यहां का नजारा बेहद खूबसूरत और मनमोहक दिखाई है। इस वॉटरफॉल के आसपास की हरियाली पर्यटकों को खूब लुभाती है। यहां पर आप ट्रैकिंग और हाईकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

रानी तालाब

बता दें कि रीवा में स्थित रानी तालाब अपनी खूबसूरती के अलावा ऐतिहासिक वजहों से भी पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। बताया जाता है कि यह राज्य के सबसे पुराने तालाब में से एक है। दिवाली आदि के मौके पर तालाब के किनारे दीपक भी जलाए जाते हैं।

वहीं रानी तालाब के पास एक काली मंदिर भी है, जो इच्छा पूरी करने वाला मंदिर माना जाता है। पर्यटक इस तालाब के किनारे सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। मानसून के समय इस तालाब की खूबसूरती देखने लायक होती है। वहीं बारिश के मौसम में आप यहां पर कई प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं।

जरूर देखें सफेद बाघ

रीवा की खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों को देखने के साथ ही यहां के सफेद बाघ देखना न भूलें। बता दें कि रीवा में स्थित मुकुंदपुर को वनों का घर माना जाता है, जो काफी चीजों के लिए फेमस है। मुकुंदपुर के वनों को सफेद बाघों का घर भी माना जाता है।

बताया जाता है कि रीवा में मुकुंदपुर के वन एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां पर आप सफेद बाघों को करीब से देख सकते हैं। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए मुकुंदपुर के वन जन्नत से कम नहीं है। ऐसे में आप यहां आने के बाद सफेद बाघ जरूर देखें।

रीवा फोर्ट

रीवा के इतिहास को करीब से देखने के लिए आपको रीवा फोर्ट का दीदार जरूर करना चाहिए। 13वीं शताब्दी में इस भव्य फोर्ट का निर्माण हुआ था। इस किले का निर्माण बघेल राजपूतों ने करवाया था। वहीं मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में इस किले का विस्तार किया था।

यह किला पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। ऐसे में इस फोर्ट को देखने के लिए हर रोज पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इस फोर्ट के किनारों पर बहने वाली नदियां किले की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। हालांकि इस फोर्ट को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इसके अंदर एक मस्जिद भी है।

भारतभूमि से अन्याय और अत्याचार को कुचलने, न्याय और सत्य की पालकी पर सवार हो कर आ रही हैं माँ शेरों वाली : डॉ उमेश शर्मा

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए महाशक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए : डॉ उमेश शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष-अ.भा.विप्र एकता मंच

संजय साग़र सिंह।

शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही हमारी सनातनी संस्कृति के शीतकालीन त्योहारों का आरंभ हो जाता है। न्यू भारत में माँ शेरों वाली के साधक सम्पूर्ण विश्व के कल्याण और सुख, शांति एवं खुशहाली के लिए महाशक्ति की भक्ति में लीन हैं। इस वर्ष ये महोत्सव गुरुवार 3 अक्टूबर को जय माता दी और जय अंबे के उद्घोष के साथ आरम्भ होने जा रहा हैं।

इस पावन-पवित्र अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के अध्यक्ष डॉ उमेश शर्मा ने महाशक्ति माँ भगवती के सभी रूपों की आराधना - उपासना के महापर्व की सभी को अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भारतभूमि से अन्याय और अत्याचार को कुचलने, न्याय और सत्य की पालकी पर सवार हो कर माँ शेरों वाली आ रही हैं। इस शुभ अवसर पर हम माँ शेरो वाली से देश - प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि और जीव मात्र के सम्पूर्ण कल्याण की कामना करते हैं। महाशक्ति की कृपा सम्पूर्ण विश्व पर बनी रहे। माँ जगत जननी जगदम्बा सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और यश प्रदान करें, और चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो। शक्ति स्वरूपा माता जगदंबा की अनुकंपा से सभी का जीवन आरोग्यता से परिपूर्ण हो। मां जगदंबा की कृपा से संपूर्ण विश्व में अन्याय और अत्याचार समाप्त हो, एवं सद्भावना का संचार हो और माँ महाशक्ति की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, चहुंओर शांति और खुशहाली हो, आदिशक्ति माँ भगवती से यही हमारी प्रार्थना है।

श्री शर्मा ने आगे कहा, नवरात्र में मां भगवती का आह्वान अत्यंचारियों और दुष्टआत्माओं का नाश करने के लिए किया जाता है। समय-समय पर अलग-अलग स्वरूप धारण कर न्याय और सत्य के दो पैरों पर माँ जगदंबा अन्याय और अत्याचारी सरों को कुचलने इस पृथ्वीलोक पर आ कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तों द्वारा श्रद्धा समर्पण भाव से मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से मां भगवती लोक कल्याण करती है और जीवन में शांति स्थापित करती है। नारी शक्ति का यह पर्व हमें मद, मत्सर व आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त करने की सीख देता हैं। नवरात्रि का आयोजन देवी के नौ स्वरूपों के माध्यम से शक्ति, ज्ञान तथा ऐश्वरय के तीन महत्वपूर्ण पक्षो को प्रगट करता हैं। मां दुर्गा की पूजा से हम पर देवी शक्ति की कृपा होती है और हम सभी संकटों, रोगों, दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से बच पाते हैं। इसके अलावा शारीरिक तेज में वृद्धि होती है। मन निर्मल व आत्मिक, दैविक, भौतिक शक्तियों का लाभ मिल पाता है। प्रत्येक नर नारी जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े हैं, वे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं देवी मां की उपासना करते ही है। फिर चाहे व्रत रखें, मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें या अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार कर्म करते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तों द्वारा श्रद्धा समर्पण भाव से मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से मां भगवती लोक कल्याण करती है और जीवन में शांति स्थापित करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मां भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए।

छीजती संवेदना

विजय गर्ग

शोक एक सामाजिक मूल्य है, जिसे अभिव्यक्त करने के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। आज सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र की किसी प्रसिद्ध हस्ती के देहांत की खबर पर नजर जाए और उस खबर पर टिप्पणियों वाले हिस्से में देहांत का उपहास करते हुए लोग पाए जाएं तो यह संवेदना के प्रति गहरा शोक पैदा कर देता है। भारतीय मूल्य तो किसी अनजान अर्थी या जनाजे का सम्मान करने वाले हैं, न कि मृत्यु का उपहास करने वाले। मगर इस दौर में किसी के निधन उपरांत ऐसे दृश्य आम हो गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया मंचों पर विदा हो चुके व्यक्ति का उपहास उड़ाया जा रहा हो।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता। यह तथ्य आज भी उतना ही सत्य है, लेकिन समय के साथ संशोधित हो गया है। इस दौर में मनुष्य वह सामाजिक प्राणी बन गया है जो सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकता। सुख, दुख की समस्त अनुभूतियों को वह सबसे पहले आभासी मंच पर ही साझा करता है। अपनी दिनचर्या, खान-पान, रहन-सहन आदि विषयों के बारे में चर्चा से उसका आभासी मंच समृद्ध रहता है। देश-दुनिया की किसी भी घटना पर प्रतिक्रियाओं की दौड़ में बेलगाम घोड़े की तरह वह भाग पड़ता है। कई दफा असत्य को सत्य और सत्य को असत्य भी मान बैठता है। मनुष्य भले समाज की वास्तविक दुनिया में रह कर सामाजिक हो या फिर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में रह कर सामाजिकता को प्राप्त करे, इन दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण उसका संवेदनशील होना है। विडंबना इसी बात की है कि इस दौर की संवेदनशीलता का परिचय सोशल मीडिया पर नित देखने को मिल रहा है। देश की किसी भी घटना, ज्वलंत विषय पर संवेदनहीन टिप्पणियां प्रचुर मात्र में दिख जाती हैं। प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखने वाले राष्ट्र में सोशल मीडिया पर किसी की बीमारी या फिर मृत्यु तक को नहीं बख्शा जाता। जब किसी के निधन उपरांत एक ओर श्रद्धांजलि का क्रम चल रहा होता है, तब दूसरी ओर मृत्यु का परिहास उड़ाने जैसी चर्चाएं भी जोर पकड़ती लगती। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है और न ही पहली दफा ऐसा हो रहा है। जब कभी कला, साहित्य, राजनीति, खेल आदि क्षेत्रों से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियों के देहावसान की खबरें आती हैं, तो इसके बाद उनके प्रति अशोभनीय टिप्पणियां और असंवेदनशील संदेशों की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ जाती है। सोशल मीडिया के ऐसे दृश्यों और इस मार्ग पर लोगों को आगे बढ़ता देख हमारी संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़े होना शुरू क्या हम वाकई मनुष्य की श्रेणी में आते हैं?

वास्तव में यह विचार किए जाने योग्य बात है कि किसी की मृत्यु किसी के लिए हास्य का कारण कैसे बन सकती है! मात्र इस आधार पर मृत्यु का मजाक बनाया जाना कि मरने वालों के विचारों से वैचारिक रूप से असहमति है, यह तथ्य शोक को हास्य में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं दे देता। जहां तक विचारों की बात है तो किसी भी मनुष्य के हर एक विचार से सभी सहमत हों, यह जरूरी नहीं है। साथ ही उसके हर एक विचार से असहमत भी नहीं हुआ जा सकता। विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर विचारों के अनुरूप सहमति और असहमति बनती बिगड़ती रहती है। विचारों की स्वीकार्यता भले न हो, लेकिन जिसे मृत्यु ने स्वीकार किया है, उसके प्रति अनर्गल बातें भी न हो।

हमारी सभ्यता और संस्कृति में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं, जिनमें शत्रुता की स्थिति में भी मृत्यु के समय संवेदना का परिचय दिया गया है। 'रामायण' में भी वर्णित है कि युद्ध के बाद मेघनाथ के शव को लंका भेजा गया था। इस तरह के अनेक प्रसंग हमने कितनी ही बार सुने हैं, लेकिन इन प्रसंगों से मिली शिक्षा को अपने जीवन में हमने कितना आत्मसात किया है, यह विचार करने योग्य है। अब 'सोशल' होने का मतलब जड़ को छोड़ना तो नहीं हो सकता! इस काल की अनेक घटनाओं पर संवेदनहीनता की बूंदें बरसती देखी गई हैं, जिससे उपजे कीचड़ में मनुष्यता घुलती जा रही है। किसी अपुष्ट खबर के आधार पर श्रद्धांजलि देकर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने वाली बातें तो लंबे समय से अक्सर चली ही आ रही है। लोगों में 'सबसे पहले हम ही' वाली होड़ की इतनी जल्दी होती है कि वे खबर की वास्तविकता की जांच ही नहीं करते। मृत्यु के खंडन की जब तक सूचना आती है तब तक शोक संदेश और श्रद्धांजलि का दौर प्रारंभ हो चुका होता है। दरअसल, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी असत्य, भ्रामक बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होते। परसाई कहते

थे कि झूठ को बार-बार कहने पर वह सच मान लिया जाता है। इस समय इन आभासी मंचों की यही स्थिति हो गई है। तर्कों और तथ्यों का स्थान बहस और विवाद ने ले लिया है। ऊर्जा और श्रम ऐसे गैरजरूरी विवादों में व्यय हो रहे हैं, जहां समय व्यर्थ करने के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होगा। आभासी अहं इतना हावी हो गया है कि जीवन के वास्तविक रिश्तों पर इसका असर तक देखने को मिल रहा है। हम तेजी से असंवेदनशील समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की असंवेदनशीलता से उपज रही शाब्दिक हिंसा बड़ा रूप धारण करें, इसके पहले इसे रोका जाना होगा। मानवता की पहचान उसकी संवेदनशीलता से है, न कि संवेदनहीन बनने से।

स्ट्रेस दूर करने के लिए रोजाना करें इन दो चाय का सेवन, वापस आ जाएगी चेहरे की मुस्कुराहट

तुलसी और अश्वगंधा की चाय का सेवन करने से स्ट्रेस कम होता है। ये दोनों चाय स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में कारगर मानी जाती हैं। ऐसे में आज हम आपको इन दो चाय के बारे में बताने जा रहे हैं।

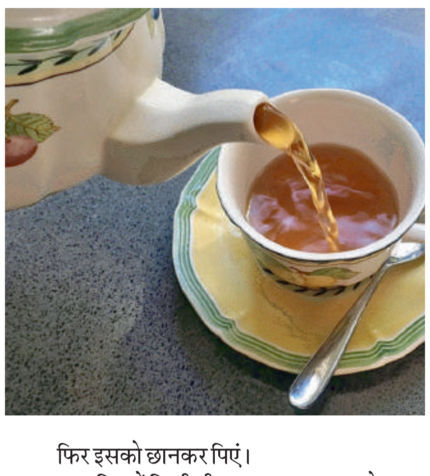

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी को किसी न किसी बात का स्ट्रेस जरूर रहता है। कभी ऑफिस का तो कभी रिलेशनशिप का तो कभी आगे बढ़ने का। जिंदगी की उलझनें कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं और न चाहते हुए भी स्ट्रेस हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। अक्सर जब हम किसी को तनाव में देखते हैं, तो कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो ऐसा करने से कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन असल में यह हमारे हाथ में होता ही नहीं है।

तनाव के कारण हमारे शरीर में कई समस्याएं होने लगती हैं। कई हर्ब्स तनाव, एंग्जायटी और चिड़चिड़ेपन को कम करने में सहायक होते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक दो चाय को अपनी डाइट में शामिल कर आप तनाव को दूर भगा सकती हैं। ये दोनों चाय स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में कारगर मानी जाती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन दो चाय के बारे में बताने जा रहे हैं।

तुलसी की चाय

तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इस चाय का सेवन करने से तनाव दूर होता है।

अगर आप रोजाना तुलसी की चाय का सेवन करने से तो बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल कम हो सकता है।

इसके पत्तों में एंटी-स्ट्रेस गुण मौजूद होता है, जो चिड़चिड़ेपन और तनाव को कम करता है।

तुलसी की चाय पीने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है और अच्छी नींद आती है।

सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों में भी यह चाय फायदेमंद होती है।

एक कप पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियों को डालकर उबालें।

फिर इसको छानकर पिएं।

आप दिन में किसी भी समय इस चाय का सेवन कर सकती हैं।

अश्वगंधा चाय

अश्वगंधा की चाय तनाव को कम करने और अच्छी नींद लाने में सहायक होती है।

इसमें एंटी-स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं। इस चाय का सेवन करने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम होता है।

अश्वगंधा चाय पीने से दिमाग शांत होता है और चिंता व एंग्जायटी दूर होती है।

साथ ही इस चाय को पीने से नींद अच्छी आती है।

नींद आने में मुश्किल होने पर इस चाय को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

शाम या रात के समय इस चाय को पीने से थकान दूर होती है और तनाव कम होता है।

इस चाय को बनाने के लिए 2 कप पानी में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर अच्छे से उबाल लें।

फिर जब यह आधा रह जाए, तो इसको छानकर सेवन करें।

शाम या रात के समय यह चाय पीना अधिक फायदेमंद होता है।

एक बार दूध और सोडा में रात भर गंदे कपड़े भिगोने से क्या होता है? इस क्लीनिंग हैक्स को जरुर ट्राई करें

कई बार कपड़ों पर गंदे दाग लग जाते हैं, जिन्हें रिमूव करना काफी मुश्किल होता है। अक्सर गूगल पर लोग सर्च करते हैं गंदे कपड़े धोने के कई सारे हैक्स। क्या आप जानते हैं कि दूध में कपड़े भिगोने से क्या होता है। यह एक ट्रेंडिंग हैक है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं।

सफेद कपड़ो पर गंदे दाग लग जाएं तो उसे धुलना काफी मुश्किल होता है। बार-बार सफेद कपड़े धोने से कपड़ों की चमक चली जाती है। पसीना और बार-बार धोने के कारण उन पर दाग या पीलापन आ जाता है। अगर आप सही तरीके और कुछ अलग हैक्स से अपने कपड़ों की चमक वापस पा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक फ्रेश बनाए रख सकते हैं। आज हम आपको इस लेख में ऐसे ही टिप्स बताने जा रहे हैं।

कपड़े धोने से पहले प्री-ट्रीट करें

सबसे पहले आप सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग कर लें। ऐसा करने से सफदे कपड़ों की चमक फीकी पड़ सकती है। कपड़े धोने से पहले किसी भी दाग को पहले से ट्रीट करें। दाग वाले एरिया पर बेकिंग सोडा और पानी का एक साधारण घोल गलाकर उसे कम करें।

ठंडे पानी और डिटर्जेंट का प्रयोग

सफेद कपड़ों को गर्म पानी में धोने से कभी-कभी दाग जम सकते हैं और कपड़े खराब हो सकते हैं। आप गुनगुने पानी और सफेद कपड़ों के लिए डिजाइन किए गए हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, ठंडा पानी कपड़ों को समय के साथ घिसनो और रंगहीन होने से बचाता है।

मशीन को ओवरलोड करने से बचें

वॉशिंग मशीन में ज्यादा कपड़े डालकर उसे ओवरलोड करने से ठीक से सफाई नहीं हो सकती है। अपने सफेद कपड़ों को आसानी और अच्छी तरह से साफ होने दें और यह ध्यान रखें कि मशीन ज्यादा भरी हुई न हो। इससे गंदगी अच्छी से साफ होती है।

सफेद कपड़ों के चमकाने के लिए दूध में भिगोएं

दूध का प्रयोग सफेद कपड़ों को ब्राइट करने के लिए किया जा सकता है, खास तौर पर लेस, सिल्क या कॉटन जैसे नाजुक कपड़ों को। दूध में मौजूद एंजाइम और प्रोटीन दाग हटाने और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना कपड़ों को चमकाने में मदद करता है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने सिविल लाइंस में दिल्ली के सभी अखाड़ों को सम्मानित किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली :संयुक्त पुलिस आयुक्त (एंटी करप्शन) मधुर वर्मा ने सिविल लाइन में दिल्ली पुलिस की मेस में दिल्ली के सभी कुश्ती अखाड़ों के मुख्य को बुलाकर सम्मानित किया, जिसमे सभी पहलवानों ने भाग लिया व कुश्ती को कैसे बढ़ावा दिया जाये क्यों कि कुश्ती पहले से कम होती जा रही है इस विषय पर अपने विचार रखे।

इस अवसर पर मधुर वर्मा ने कहा कि कुश्ती से न केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मैंने देखा है कि मैच में असफल होने के बाद भी पहलवान विनम्र, आत्मविश्वासी और आत्म-सुधार के प्रति समर्पित रहते हैं उन्होंने यह भी कहा कि वह खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर भारतीय शैली कुश्ती संघ के महासचिव और एरा फाउंडेशन के चेयरमैन रिंकू आर निगम, अध्यक्ष अंकुश अग्रवाल, चेयरमैन बब्बू खलीफा, अर्जुन अवार्डी राजीव तोमर और कई उस्तादों और खलीफाओं ने मधुर वर्मा को कुश्ती की पहचान मानी जाने वाली चांदी की गदा भेंट की। वरिष्ठ पत्रकार एवं एरा फाउंडेशन के महासचिव डॉ. सुनील पाराशर ने वर्मा के साथ एरा फाउंडेशन स्मारिका 2024 का पोस्टर जारी किया।

भाजपा ने संसद के अंदर से महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाकर उनका अपमान किया- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय के पास लगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही भाजपा पर तीखा हमला बोला है। ''आप'' के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि देशभक्तों, शहीदों और राष्ट्र का अपमान करना भाजपा के रग-रग में बसा है। भाजपा अपने इस आदत को बरकरार रखते हुए 1857 की योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने का कुचक्र रच रही है। इनके पुरखों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों की जासूरी की थी और आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 53 साल तक तिरंगा नहीं फहरा कर देश से गद्दारी की। वहीं, मोदी जी ने संसद से महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर और शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाकर उनका अपमान किया। हम लोग पूरी दिल्ली में मुहिम चलाकर भाजपा और आरएसएस को बेनकाब करेंगे और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने नहीं देंगे।

बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा ने अपना चरित्र नहीं बदला है। इसी चरित्र के चलते भाजपा और उनके पुरखे देश के लिए मर-मिटने वाले शहीदों का बार-बार अपमान करते हैं। भाजपाई 1857 की शहादत का अपमान करते हैं। भाजपा के लोग बार-बार वही चरित्र दिखाते हैं, जो इनके पुरखों ने आजादी के आंदोलन में दिखाए थे। आजादी के आंदोलन में भाजपा वालों के पुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों की जासूसी की और उनके खिलाफ काम किया था। आज वही काम देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि विरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति आरएसएस मुख्यालय के सामने लगी हुई है। आरएसएस और भाजपा को बर्दाश्त नहीं है कि देश के लिए कुर्बानी देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी हुई है। भाजपा के लोग कुचक्र रचकर लक्ष्मीबाई की मूर्ति को आरएसएस मुख्यालय के पास से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को आगाह करना चाहता हूं कि देशभक्तों का अपमान देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी है। भाजपा की गद्दारी का इतिहास पूरा देश जाना है। आरएसएस ने 53 साल तक अपने मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा नहीं फहराया। जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उनके खिलाफ अदालत में 12 साल तक लड़ाई लड़ी। ये लोग तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते हैं।

उन्होने बताया कि संसद के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉ. अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जहां प्रतिमा लगी थी, उसे देखने और नमन करने के लिए पूरे देश के लोग आते थे। लेकिन इन्होंने वहां से इन महापुरुषों की प्रतिमाएं हटा दी। भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर भी महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉ. अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। अब दिल्ली में 1857 की योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग इस मुद्दे को जगह-जगह बताएंगे कि देशभक्तों का अपमान देशद्रोह है और यह देशद्रोह दिल्ली के अंदर भाजपा खुलेआम करने जा रही है।

संजय सिंह ने कहा कि हम लोग दिल्ली के अंदर मुहिम चलाकर भाजपा और आरएसएस के लोगों को बेनकाब करेंगे। लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने नहीं देंगे। इन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देश के साथ गद्दारी की। आजादी मिल गई तो 53 साल तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा न फहरा कर देश के साथ गद्दारी की। फिर संसद के अंदर से हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हटा दी और अब दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। भाजपा देश के लोगों को बताएगी कि हम लोग किसकी प्रतिमा लगाएं। क्या हम उन गद्दारों की प्रतिमा लगाएं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। अगर आरएसएस मुख्यालय के सामने से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाई गई तो पूरी दिल्ली में भाजपा को बेनकाब करेंगे। साथ ही हरियाणा में भी इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाएंगे। भाजपा का यह कृत्य अक्षम अपराध और देशद्रोह है।

दो दिवसीय सत्र में आतिशी दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर चर्चा करें: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 26 सितम्बर से शुरु होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में रहने के कारण पिछले 8 महीनां से कोई कैबिनेट की बैठक भी नही हुई है, जिससे पिछले एक साल से भी अधिक समय से दिल्ली की मासूम जनता की परेशानियों का हल निकालने के लिए कोई फैसला नही लिया गया।

यादव ने कहा कि आतिशी को उपराज्यपाल के निर्देशानुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में 11 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, जो केजरीवाल सरकार के अपारदर्शी वित्तीय लेनदेन को उजागर करेंगी। विभिन्न विभागों द्वारा धन के दुरुपयोग का मामला सार्वजनिक हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शपथ समारोह के बाद पहले प्रेसवार्ता, जंतर मंतर पर लगने वाली अदालत की तरह कहीं विधानसभा सत्र भी अरविन्द केजरीवाल को महान बनाने का मैदान बनकर न रह जाए।

उन्होने कहा कि विधानसभा सत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने, टूटी सड़कों की कार्पेटिंग, नालों और सीवरों से गाद निकालने के मामले, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने, नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार, बुर्जुगों

विधवाओं की पेंशन, पानी की कमी, बढ़े हुए बिजली बिल, जल जनित डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी जनित बीमारियाँ को नियंत्रित करने के लिए सहित ऐसे अन्य मुद्दे के तत्काल उपाय करने पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षो में उद्देश्य विहीन और दिशाहीन की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री सिसौदिया और अत्यधिक मंत्री और विधायक खुद को जेल से बचाने के लिए अदालती मुकदमे लड़ने में व्यस्त हैं।

'मुख्यमंत्री को दिलाएं याद', दिल्ली के LG का कैग रिपोर्ट को लेकर मुख्य सचिव-वित्त सचिव को पत्र

सुषमा रानी

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र लिखकर 12 लंबित कैग रिपोर्ट को सदन में पेश करने का निर्देश दिया है। एलजी सचिवालय ने आप सरकार पर अलग-अलग विभागों की कुल 12 कैग रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं जिसमें दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति और उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से एक दिन पहले एक बार फिर से एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव को पत्र लिखकर लंबित 12 कैग रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का निर्देश दिया है। एलजी वीके सक्सेना के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने पत्र में लिखा है कि कैग की ये 12 रिपोर्ट वर्ष 2021-22 तक की लंबित हैं।

एलजी सचिवालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) शासित दिल्ली सरकार पर अलग-अलग विभागों के कुल 12 कैग रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। कुंद्रा ने इस पत्र में सरकार के वित्त, प्रदूषण, जनस्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित विभागों के खातों से संबंधित कुल 12 कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास लंबित होने की बात कही है।

आबकारी नीति की ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुई पेश

इनमें से कुछ कैग रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति और उसकी ऑडिट रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है जिसे सदन पटल पर रखा नहीं गया है। एलजी सचिवालय ने सभी रिपोर्ट को सदन में पेश करने का निर्देश दिया है।

राजनिवास ने यह भी साफ किया है कि उन्हें कैग से 18 जुलाई और 19 सितंबर 2024 को पत्र मिले हैं, ताकि इन रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सके।

एलजी पहले भी उठा चुके हैं मामला

बता दें कि उपराज्यपाल द्वारा सभी लंबित कैग रिपोर्ट को सदन में रखने में देरी का मामला कई बार वित्त विभाग, दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया है। हालांकि, इन कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखने का कोई प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा एलजी को अभी तक नहीं मिला है, जो संवैधानिक रूप से इन्हें विधानसभा में रखे जाने का आदेश देते हैं।

ऑड-ईवन लगा तो व्यापारी करेंगे विरोध - परमजीत सिंह पम्मा

सुषमा रानी, दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। जिसको लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है। सर्दियों में आने वाले समय में अगर प्रदूषण बढ़ा तो ऑड-ईवन लागू हो सकता है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने दिल्ली सरकार चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा निर्णय करती है तो व्यापारी उसका विरोध करेंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में त्योहारों के दिन है और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसमें व्यापार में बुरा असर पड़ेगा। जिससे बाहर का व्यापारी दिल्ली से बाहर से खरीदारी कर लेता है और करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली के व्यापार का होता है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा सरकार कोई भी निर्णय करने से पहले व्यापारियों को भरोसे मिले। क्योंकि पूरे वर्ष मंद का दौड़ रहा है। उसके बाद और ओड एंड इवन से व्यापार में काफी असर पड़ेगा। पम्मा ने कहा जबकि सरकार पूरे वर्ष पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ नहीं करती। जब भी कभी पॉल्यूशन की बात आती है। यह और ओड एंड इवन लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब व्यापारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

DUSU चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जताई सख्त नाराजगी; कुलपति को लेकर भी कही अहम बात

DUSU Election 2024 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पता चला है कि उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस मामले में पीठ ने विश्वविद्यालय के कुलपति से हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने को कहा है। पढ़िए आखिर पीठ ने और क्या-क्या कहा है?

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से नाराज दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, धन शोधन का नहीं।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पीठ ने मौखिक रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति से हस्तक्षेप करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि लोग शिक्षा के स्थान पर ₹अनपढ़ों की तरह व्यवहार₹ कर रहे हैं और कहा कि चुनाव प्रणाली युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए नहीं है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरों को देखते हुए पीठ ने कहा कि डीयूएसयू चुनाव के दौरान स्थिति आम चुनावों से भी बदतर थी। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय को 27 सितंबर को होने वाले चुनाव स्थगित कर देने चाहिए या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर नए सिरे से नामांकन शुरू करना चाहिए या मतदान की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन सभी तरह के नुकसान को दूर किए जाने तक परिणाम घोषित नहीं करना चाहिए।

विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी, जो अदालत में मौजूद थे, के निर्देश पर विश्वविद्यालय के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाए, क्योंकि अधिकारी तब तक इस पर निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं।

दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया

इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली मेट्रो के साथ सहयोग करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक संपत्ति को और नुकसान न पहुंचे और जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उसे हटाया जाए।

नाराज पीठ ने कहा, "इन चुनावों में लोगों के पास बहुत पैसा है। यह लोकतंत्र का उत्सव है, न कि धन शोधन का उत्सव। यह धन शोधन है, जो चल रहा है। यहां कुछ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।"चुनाव प्रणाली युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए नहीं है। शिक्षा के स्थान पर लोग अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। केवल एक अनपढ़ ही इस तरह का व्यवहार कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर रहा है।

कुलपति को आज ही बैठक बुलानी चाहिए

पीठ ने कहा कि सख्त कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों को पता चले कि वे इस तरह से बच नहीं सकते। इससे पता चलता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। कुलपति को आज ही बैठक बुलानी चाहिए।" इसमें कहा गया, "यह भ्रष्टाचार के बराबर है। अगर छात्र इस स्तर पर भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है।"

अदालत संभावित डीयूएसयू उम्मीदवारों और छात्र राजनीतिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो सार्वजनिक दीवारों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें गंदा करने, गंदा करने या नष्ट करने में शामिल हैं।

याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा, जो एक पेशेवर वकील हैं, ने कक्षाओं को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण और भ्रष्टाचार से मुक्त परिवेश से वंचित किया जा रहा है और साथ ही छात्रों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को निर्देश देने की भी मांग की कि वे भ्रष्टाचार को हटा दें और क्षेत्रों का नवीनीकरण करें और नष्ट हुए हिस्सों के सौंदर्यीकरण के लिए आगे प्रयास करें।

सुनवाई के दौरान, डीयू के वकील ने कहा कि दोषी उम्मीदवारों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।

एमसीडी के वकील ने क्या कहा...

एमसीडी के वकील ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बड़ी संख्या में पोस्टर, बैनर और अन्य सामान हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है।

दिल्ली क्राइम रिपोटर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी गठित

सुषमा रानी

दिल्ली क्राइम रिपोटर्स एसोसिएशन की एक बैठक वरिष्ठ पत्रकार ललित वत्स के संरक्षण में आयोजित की गई। जिसमें क्राइम रिपोटिंग के दौरान अपराध संवाददताओं को आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विर्भन्नि टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों से जुड़े क्राइम रिपोर्टस के साथ क्राइम बीट पर काम करने वाले कुछ सीनियर पत्रकार भी शामिल हुए। जिसमें समाचार संकलन के दौरान क्राइम रिपोटर्स को होंने वाली परेशानियों और विभिन्न मुद्दो पर चर्चा और निवारण के लिए सर्वसम्मति से एक कार्यकारिणी गठित की गई। कार्यकारिणी को क्राइम रिपोटर्स की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ समाचार संकल्न से जुड़ी समस्याओ के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सीबीआई, ईडी और सभी अद्धसैंनिक बलों के आधिकारिक प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया। पुलिस और क्राइम रिपोटर्स के बीच बेहतर रिश्तों के लिए कार्यकारिणी को विचार करने व फैंसले लेने के लिए भी अधिकृत किया गया।

दिल्ली क्राइम रिपोटर्स की नवगठित कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारियों को नामित किया गया ललित वत्स को संरक्षक एवं सलाहकार तथा अध्यक्ष जोगेन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अतुल भाटिया, आनंद तिवारी, जितेन्द्र शर्मा, विजय शर्मा, तथा महासचिव राजीव निशाना, कोषाध्यक्ष दिनेश वत्स, सचिव अनुज मिश्रा, अरविन्द ओझा, शंकर आन्नद, संजीव यादव, संगठन सचिव सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव पुरूषोत्तम वर्मा, राकेश रावत, सह सचिव पुनित शर्मा के अलावा 11 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं, अमलेश राजू, कृष्ण कुनाल सिंह, शिवेन्द्र, मनोज टंडन, गाजियाबाद से जितेन्द्र बच्च्चन, शक्ति सिंह, नोएडा से दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा से रविन्द्र जयंत, गुरुग्राम से दीपक शर्मा के अलावा प्रेस सचिव रविन्द्र कुमार को बनाया गया।

कुछ ऐसा होगा यूपी का फ्यूचर: नोएडा-गाजियाबाद सहित आसपास के शहर होंगे जाम से मुक्त, 50 साल के लिए 9 बिंदुओं पर तैयार होगा प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आगामी 50 वर्षों के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना विकास गाजियाबाद हापुड़ बुलंदशहर के यातायात को बेहतर बनाने के लिए रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार किया जाएगा। इस योजना में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से लेकर नए फ्लाईओवर बाटलनेक और परिवहन प्रणाली को ध्यान में रखा जाएगा। यह प्लान दिल्ली फरीदाबाद गुरुग्राम से बेहतर कनेक्टिविटी देगा।

नोएडा। चार जिलों के छह शहरों को यातायात जाम मुक्त बनाने के लिए रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार किया जाएगा। यह प्लान नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के यातायात को दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम से बेहतर कनेक्टिविटी देगा।

प्लान को बनाने के लिए एक सलाहकार कंपनी का चयन किया जाएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से इस प्लान को तैयार करने के लिए नोएडा को नोडल बनाया है।

किन बातों का रखा जाएगा ध्यान

यह रीजनल प्लान पश्चिमी यूपी में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। चयन होने वाली सलाहकार कंपनी एक ऐसा प्लान बनाएगी, जिसे सभी जिले और प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। इसमें सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से लेकर नए फ्लाई ओवर, बाटलनेक और ट्रांसपोटेशन को ध्यान में रखा जाएगा।

हापुड़ और गाजियाबाद को बाद में जोड़ा

नोएडा प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि रीजनल प्लान में पहले चार शहर शामिल थे, लेकिन अब हापुड़ और गाजियाबाद को भी जोड़ा गया है। सलाहकार कंपनी क्षेत्रीय प्लान का अध्ययन करेगी और उसमें दिए गए बेहतर प्लान या सुझाव को अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में शामिल करेगी।

जल्द मांगा जाएगा प्राथमिक प्लान

सलाहकार कंपनी को अधिकतम डेढ़ साल का समय दिया जाएगा, लेकिन तीन माह में उसे प्राथमिक प्लान बनाकर देना होगा। इस पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेंगे।

आगामी 50 साल के लिए होगा प्लान

यह एक प्रकार का थिंक टैंक होगा, जिसमें छह स्थानों के अधिकारियों और सलाहकार कंपनी अध्ययन करेंगे कि आगामी 50 सालों तक दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्र को कैसे जाम मुक्त बनाया जाए। जितने भी सुझाव आएंगे कंपनी प्लान में शामिल करेगी। सुझाव पर अमल करने का काम संबंधित प्राधिकरण का होगा।

नौ बिंदुओं पर तैयार होगा सीएमपी

- सलाहकार कंपनी तीनों शहर के लोकल अथॉरिटी के प्लानिंग सेल से बात करेगी। विजिट करके शहरी और ग्रामीण इलाकों की एक ब्रीफ तैयार करेगी, जिसमें लोकेशन, लैंड एरिया, रोड नेटवर्क, रीजनल इकनॉमिक, स्ट्रक्चर उपलब्धता को शामिल किया जाएगा।
- सभी प्रकार का डाटा एनालिसिस रिपोर्ट को एकत्रित करना, जिसमें सामाजिक परिवेश, रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट नियम, रीजनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, नेशलन और स्टेट रूल, सड़क हादसे, लैंड यूज, मैप शामिल है।
- एक प्राथमिक सर्वे प्लान तैयार किया जाएगा।
- हितधारक, पब्लिक और अन्य लोगों से इस सर्वे प्लान पर बातचीत की जाएगी।
- डिटेल सर्वे होगा, जिसमें निर्मित इमारतों की संख्या, ट्रैफिक, रोड पर स्पीड, पार्किंग, पेडेसट्रियन का डाटा लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की जाएगी, जो टाइम, कास्ट, कंफर्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से तैयार की जाएगी।
- महत्वपूर्ण बिंदु प्रदूषण से संबंधित भी होगा। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का डाटा लेकर चेक किया जाएगा कि इसका कितना असर प्लान के अनुसार कम होगा या बढ़ेगा।
- नोएडा ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र में ई-बस चलाने का प्रावधान है। इसे मोबिलिटी प्लान में ही शामिल किया जाएगा। इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जिसमें एडमिन ब्लॉक, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, वार्क शॉप आदि।
- रोड नेटवर्क, इंटर कनेक्टिविटी, पार्किंग उपलब्धता और उसके प्रकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैरा ट्रांजिस्ट सिस्टम, सड़कों पर ट्रैफिक का भार, ट्रैफिक सेफ्टी को शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
- फाइनल ड्राफ्ट कंपनी गठित की गई समिति के सामने रखेगी, बोर्ड से अप्रूव होने पर इस पर काम शुरू किया जाएगा।

छापा पड़ते ही मचा हड़कंप, मौके से 3 गिरफ्तार; लाखों रुपये की नकली दवाइयां बरामद

Haryana News मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ड्रग्स विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम में मोहम्मदिया फार्मेसी में छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया और लाखों रुपये की नकली दवाइयां बरामद की हैं। टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां-कहां पर ये दवाइयां सप्लाई की जा रही थी।

गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 39 स्थित मोहम्मदिया फार्मेसी में आर्थराइटिस बीमारी में काम आने वाली सिप्ला कंपनी की टोफाजेक-5 नाम से नकली दवा बेची जा रही थी। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, ड्रग्स विभाग और सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से फार्मेसी में बुधवार को छापा मारा। इस दौरान सिप्ला कंपनी के डायरेक्टर कार्पोरेट अफेयर को भी मौके पर बुलाया गया।

वहीं, फार्मेसी से बरामद दवाई चेक करने पर नकली पाई गई। जांच करते हुए फार्मेसी संचालक समेत सप्लाई करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की ओर से बताया गया कि काफी दिनों से सूचनाएं मिल रही थीं कि सेक्टर 39 में एक फार्मेसी पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। जब संयुक्त टीम मोहम्मदिया फार्मेसी पर पहुंची तो इसका मालिक नूंह के घसेड़ा गांव निवासी यूसुफ मिला। फार्मेसी पर जांच के दौरान सिप्ला कंपनी की टोफाजेक-5 एमजी गोली की 50 डिब्बी मिली। इसमें एक डिब्बी में 60 गोलियां होती हैं। इस दवाई का कोई बिल भी यहां से नहीं मिला।

बता दें कि सिप्ला कंपनी की यह दवा आर्थराइटिस बीमारी में काम आती है। दवाई नकली होने के शक पर कंपनी के डायरेक्टर कार्पोरेट अफेयर को मौके पर बुलाया गया। फार्मेसी से बरामद दवाई चेक करने पर नकली पाई गई।

पूछताछ में पता चला कि नूंह के संलभा गांव निवासी नसीम फार्मेसी में यह दवाई सप्लाई करता है। निशानदेही पर सेक्टर 39 स्थित किराए के मकान में छापेमारी कर नसीम को भी पकड़ लिया गया। इस मकान से 964 डिब्बी बरामद की गई। इसकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपये बताई गई। नसीम के एक अन्य साथी नूंह के करेरा गांव निवासी जुबेर को भी सेक्टर 39 से हिरासत में लिया गया। यह भी दवाई सप्लाई करने के काम में इनकी मदद कर रहा था।

डिमांड के हिसाब की जा रही थी सप्लाई

पूछताछ में पता चला कि डिमांड के हिसाब से दवाई आगे बेची जाती है। इन दवाइयों को सप्लायर 500 रुपये प्रति डिब्बी के हिसाब से देता था। 690 रुपये में फार्मेसी को दी जाती थी। फार्मेसी संचालक इस दवाई को 900 रुपये में मरीजों को बेचते हैं। जबकि इस दवाई की असल कीमत 1200 रुपये है। आरोपित यूसूफ 12वीं पास है। वर्ष 2018 से सेक्टर 39 में मोहम्मदिया फार्मेसी चला रहा था। मोहम्मद नसीम भी 12वीं पास है। यह दवाइयों की सप्लाई करता था और जुबेर पांवी पास है। यह जून 2024 से दवाई सप्लाई में इनकी मदद कर रहा था।

पांच दिन के रिमांड पर आरोपित

आरोपितों से तीन मोबाइल फोन व फार्मेसी संचालक से दो लाख 67 हजार रुपये की नकदी बरामद की गई। सदर थाने में मेडिकल एक्ट की धारा 18(सी), 18ए, 18बी व 17बी ड्रग्स व कास्मेटिक एक्ट 1940 के तहत केस दर्ज किया गया। अदालत में पेश करके यूसुफ, नसीम को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। जुबेर को भोंडसी जेल भेजा गया।

सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अमित ने बताया कि आरोपितों से पता किया जाएगा कि यह नकली दवाई कहां पर बनाई जाती हैं और इन दवाइयों को कहां-कहां पर सप्लाई किया जाता है। दवाइयों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। ड्रग्स विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर को सील कर उनके लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जांच ड्रग्स विभाग की ओर से की जा रही है।

गाजियाबाद में आशियाना बसाने का सुनहरा मौका, नई टाउनशिप ला रहा GDA, योजना में खर्च होंगे 15 हजार करोड़ रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

Harnandipuram Housing Project अगर आप गाजियाबाद में अपना आशियाना बसाना चाह रहे हैं तो जीडीए आपके लिए सुनहरा मौका ला रहा है। जीडीए ने आखिरी बार 2004 में एक आवासीय योजना विकसित की थी जिसे मधुबन बापूधाम आवासीय परियोजना कहा जाता है। अब हरनंदीपुरम नाम से करीब 15 हजार करोड़ रुपये की नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा।

गाजियाबाद। नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाने के लिए जीडीए अधिकारियों के साथ वीसी अतुल वत्स ने बैठक की, जिसमें टाउनशिप की बाउंड्रीवाल का निर्धारण किया गया। बाउंड्रीवाल के भीतर आने वाली जमीन के काश्तकारों, गाटा, खतौनी की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रॉपर्टियों की होगी यूनिक आईडी

एक हफ्ते में शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहां से मंजूरी होने पर टाउनशिप को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ होगी। हरनंदीपुरम नाम से करीब 15 हजार करोड़ रुपये की नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए जीडीए ने सेटेलाइट के माध्यम से चिह्नित क्षेत्र का रैपिड सर्वे कराया जा रहा है।

मंगलवार को जीडीए वीसी अतुल वत्स ने ने अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि टाउनशिप को विकसित करने के लिए बाउंड्रीवाल का निर्धारण कर लिया गया है। इस बाउंड्रीवाल में विद्युत निगम का सब स्टेशन से होकर गुजर रही हाइटेंशन लाइन के नीचे और आसपास पार्क व ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी।

दो दिन में दी जाएगी किसानों की सूची

टाउनशिप में करीब 30 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ऐसे में जीडीए इस पूरी जमीन पर पार्क विकसित किया जाएगा। इससे भविष्य में अवैध कॉलोनी नहीं काटी जा सकेगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगले दो दिन में किसानों की सूची, भूमि गाटा संख्या और संपूर्ण क्षेत्रफल का डाटा तैयार कर रिपोर्ट दें।

उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत शासन को जाएगी। इसकी मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण और किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी।

गहराई वाली भूमि पर तालाब भी होंगे विकसित

जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि जहां ईंट भट्ठों की वजह से भूमि से मिट्टी अधिक मात्रा में निकाली गई है। यह जमीन काफी गहराई में पहुंच गई है। ऐसी कुछ जगह तालाब भी विकसित किए जाएंगे। ताकि जलस्तर में बढ़ोतरी हो सके। इसमें से और मिट्टी निकलवाकर दूसरी गहरी जगह डलवाई जाएगी। ताकि वह समानांतर हो सकें।

शमशान घाट, कब्रिस्तान और देवस्थान दर्शाए जाएंगे

हरनंदीपुरम टाउनशिप की सर्वे शीट तैयार की जा रही है। इसमें देवस्थान, शमशान और कब्रिस्तान को विधिवित रूप से दर्शाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बाद इसे विस्तारीकरण योजना के तहत इनको लेकर किसी तरह का विवाद न हो। यह नक्शे पर पूरी तरह दिखाई दे। बता दें कि पूर्व की योजनाओं में प्लॉट के निकट शमशान, कब्रिस्तान के मामले में इस तरह के विवाद सामने आए हैं।

संरक्षित हों तीर्थस्थल की हिन्दू वंशावलियों की पंजिका

अशोक मधुप

हिंदू परिवारों को इस बारे में बहुत कम या न के बराबर जानकारी है। उन्हें पता भी नही कि इन स्थानों पर उनके परिवार का इतिहास संग्रहित है। सदियों से बहियों में ये रिकार्ड व्यापारी के खाते की तरह लिखकर रखा जा रहा है।

हिंदू तीर्थस्थल धार्मिक मान्यताओं और पूजन अर्चन के लिए विख्यात है। इन सब कार्य को इन स्थलों के ब्राह्मण पंडित कराते हैं। ये ब्राह्मण पंडित पंडा कहे जाते हैं। ये पंडा सदियों से एक कार्य करते और कराते आ रहे हैं। ये पंडा अपने पास आने वाले यजमान (भक्तों) के परिवार का इतिहास अपनी बहियों में संजोते जा रहें हैं। ये काम सदियों से अनवरत रूप से जारी है। ये हिन्दू वंशावलियों की पंजिकाएं ऐतिहासिक धरोहर हैं। आज इनके संरक्षण की आवश्यक्ता है। इनके संजोकर रखने की जरूरत है।

हिंदू परिवारों को इस बारे में बहुत कम या न के बराबर जानकारी है। उन्हें पता भी नही कि इन स्थानों पर उनके परिवार का इतिहास संग्रहित है। सदियों से बहियों में ये रिकार्ड व्यापारी के खाते की तरह लिखकर रखा जा रहा है। अधिकतर भारतीयों व वे परिवार जो विदेश में बस गए उनको आज भी पता नहीं कि इन तीर्थस्थल की पंडो की बहियों में उनके परिवार की वंशावली दर्ज है। हिन्दू परिवारों की पिछली कई पीढ़ियों की विस्तृत वंशावलियां इन पंडा के पास संग्रहित हैं। ये पंडा आने वाले यजमान से उसके परिवार की जानकारी नोट करने के बाद उसके हस्ताक्षर कराकर बही में अपने पास रखते हैं। ये पंडा ये बहियां अपनी आने वाली अपनी पीढ़ी को सौंपते जाते हैं। ये बहियां जिलों व गांवों के आधार पर वर्गीकृत की गयीं हैं। प्रत्येक जिले की पंजिका का विशिष्ट पंडित होता है। यहाँ तक कि भारत के विभाजन के उपरांत जो जिले व गाँव पाकिस्तान में रह गए व हिन्दू भारत आ गए उनकी भी वंशावलियां यहाँ हैं। कई स्थितियों में उन हिन्दुओं के वंशज अब सिख हैं, तो कई के मुस्लिम अपितु ईसाई भी हैं। किसी-किसी की सात वंश या उससे भी ज्यादा की जानकारी पंडों के पास रखी इन वंशावली पंजिकाओं से होना साधारण सी बात है।

शताब्दियों पूर्व से हिन्दू पूर्वजों ने हरिद्वार या किसी पावन नगरी की यात्रा की/ तीर्थयात्रा के लिए या/ शव-दाह या स्वजनों के अस्थि व राख का गंगा जल में किया होगा तो वे संबद्ध पंडा के पास गए होंगे। ये पंडा इन आने वालों के रहने खाने तक की व्यवस्था करते हैं। इन पंडाओं ने अपनी पंजिका में वंश-वृक्ष को संयुक्त परिवारों में हुए सभी विवाहों, जन्म व मृत्युओं के विवरण दर्ज किया हुआ हैं। वर्तमान में धार्मिक स्थल पर जाने वाले भारतीय हक्के-बक्के रह जाते हैं जब वहां के पंडित उनसे उनके अपने वंश-वृक्ष को नवीनीकृत कराने को कहते हैं।

आजकल जब संयुक्त हिदू परिवार का चलन ख़त्म हो गया है। लोग एकल परिवारों को तरजीह दे रहे हैं, ये पंडित चाहते हैं कि आगंतुक अपने फैले परिवारों के लोगों व अपने पुराने जिलों- गाँवों, दादा- दादी के नाम व परदादा-परदादी और विवाहों, जन्मों और मृत्यु, परिवारों में हुए विवाह आदि की पूरी जानकारी के साथ वहां आएं। आगंतुक परिवार के सदस्य को सभी जानकारी नवीनीकृत करने के उपरांत वंशावली पंजीका को भविष्य के पारिवारिक सदस्यों के लिए व प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षरित करना होता है। साथ आये मित्रों व अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर करने की विनती की जा सकती है।

इन तीर्थ स्थल के पुरोहितों के पास देश और दुनिया भर के यजमानों का दशकों पुराना लिखित रिकॉर्ड वंशावली के रूप में मौजूद है। किसी यजमान के आने पर चंद मिनटों में ही संबंधित पुरोहित कंप्यूटर से भी तेज गति से वंशावली देखकर उनके पूर्वजों की जानकारी दे देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान इन तीर्थ स्थल पर आने वाले लोग अपने तीर्थ पुरोहितों के पास आकर वंशावली में अपने वंश के बारे में जरूर जानते हैं। ये पडे जनपद के हिसाब से हैं। तीर्थ स्थल में पहने वालों को पता है कि किस जनपद के पंडा कौन हैं। किसी दूसरे के यजमान को कोई अन्य पंडा खुद क्रिया-कर्म नहीं कराता। संबधित जिले के पंडा के पास उसे भेज देता है।

शताब्दियों से हो रहा ये लेखन भोज पत्रों और ताम्र पत्रों के बाद अब कागज की बहियों पर शुरू किया गया। तीर्थ पुरोहितों के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी बहियां आज भी सुरक्षित हैं। तीर्थ पुरोहितों की बहियों में देश भर के राजाओं, महाराजाओं, साधु, संतों, राजनेताओं एवं आम लोगों के परिवारों के वंश लेखन बहियों में मौजूद हैं। अकेले हरिद्वार में 30 हजार से अधिक की संख्या में वंशावली की बहियां सुरक्षित और संरक्षित हैं। इन बहियों में लेखन करने के लिए अलग स्याही तैयार करके तीर्थ पुरोहित वही लेखन करते हैं, जो काफी वर्षों तक सुरक्षित रहती है। इन वंशावलियों में जातियों, गोत्रों, उपगोत्रों का भी जिक्र रहता है। सबसे अहम बात इन बहियों में देखने को मिलती हैं कि तीर्थ पुरोहितों ने लेखन को भेदभाव से दूर रखा है। जहां राजाओं, महाराजाओं की वंशावलियां जिस क्रम में अंकित हैं, उसी क्रम में तीर्थ नगरी में पहुंचने वाले अन्य श्रद्धालुओं की हैं। विभिन्न राजवंशों की मुद्रांए, हस्त लेखन, दान पत्र, अंगूठे और पंजों के निशान बहियों में मौजूद हैं। यहां की वंशावलियों में देश की कई रियासतों के राजाओं के आने के उल्लेख दर्ज हैं।

अक्तूबर 2007 में हमें इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट की एक कांफ्रेंस में बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला। मेरे साथ गए मेरे दोस्त नरेंद्र मारवाड़ी भी थे। हम मारवाड़ी के साथ बद्रीनाथ में, अजमेर के महावर वालों की धर्मशाला में चले गए। ये मारवाड़ी के परिवारवालों की धर्मशाला हैं। वहां पंडित जी से बात की। वंशानुक्रम के बारे में बताया। बात करते-करते पंडित जी ने अपनी बही खोलकर उनके गोत्र का विवरण खोला तो पता चला कि मारवाड़ी के पिता जी 41 वर्ष पूर्व यहां यात्रा को आए थे। यात्रा को आने के बाद हुए उनके दो बच्चों का विवरण दर्ज नहीं थे। पंडित जी ने बही देखकर बताया कि 93 साल पूर्व उनके दादा जी बद्रीनाथ आए थे। दोनों के आने की तिथि तक वही में दर्ज थी। उनके हस्ताक्षर भी बही में मौजूद थे। मित्र को अपने बाबा का नाम ज्ञात था। यहां बही से उन्होंने अपने बाबा के पिता उनके भाई, बाबा के दादा और उनके भाइयों आदि का विवरण नोट किया। पंडित जी ने अपनी वही में मित्र से अपने और उनके बच्चे, भाई और भाइयों के बच्चों की जानकारी नोट की। नीचे तारीख, माह, सन डालकर हस्ताक्षर कराए।

सदियों से चले आ रहा इतिहास को संजोकर रखना एक दुरूह कार्य है। इस कार्य को ये पंडे सुगमता से पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। आज इस इतिहास को संजोने और संरक्षण की जरूरत है। अच्छा रहे कि इनका कंप्यूटरीकरण हो जाए। बहियों को लैमिनेट करके भी संरक्षित किया जा सकता है। कैसे भी हो, ये होना चाहिए, नहीं तो समय के साथ ये गलता और खराब होता चला जाएगा।। ये काम इनके व्यक्तिगत स्तर से संभव नहीं। सरकार को अपने स्तर से कराना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

यूलर मोटर्स हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में उतरी, एडीएएस तकनीक से लैस है मॉडल

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस सेक्टर की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनी यूलर मोटर्स हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में उतर गई है। कंपनी ने बुधवार, 25 सितंबर को दो इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन पेश किए, जिन्हें विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह एलसीवी तैयार की गई है।

कंपनी फिलहाल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बेचती है। अब कंपनी ने दो स्टॉर्म ईवी मॉडल पेश की हैं, जिन्हें खास तौर पर शहर के अंदर और बाहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यूलर मोटर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव कुमार ने कहा कि फिलहाल देश में कुल छोटे कमर्शियल वाहनों यानी एससीवी की बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है।

उन्होंने कहा कि कंपनी ओवरऑल इलेक्ट्रिक एससीवी सेगमेंट को बढ़ाना चाहेगी और फिर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में अपनी मौजूदा बाजार हिस्सेदारी के समान बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहेगी। सौरव कुमार ने कहा, "तिपहिया वाहनों में हम उन शहरों में 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सफल रहे हैं, जहां हम काम करते हैं। हम छोटे वाणिज्यिक वाहन खंड में भी इसी तरह की हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि यूलर पहले दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद जैसे सात प्रमुख शहरों में दो नए मॉडल लॉन्च करने के बाद ही अन्य शहरों में हल्के वाणिज्यिक वाहन को पेश करेगी।

कंपनी ने इंट्रा-सिटी ड्राइविंग के लिए 8.99 लाख रुपये की शोरूम कीमत पर स्टॉर्म ईवी टी1250 को लॉन्च की है। इसे एक बार चार्ज करने पर लगभग 140 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है और यह 1,250 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम है।

स्टॉर्म ईवी लॉन्गरेंज 200 भी इंट्रा-सिटी ड्राइविंग के लिए है। इसकी कीमत 12.99 लाख रुपये है। इसकी भार क्षमता भी 1,250 किलोग्राम है, लेकिन इसे एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है।

सौरव कुमार ने कहा कि दोनों मॉडल एडीएएस तकनीक और नाइट विजिबिलिटी असिस्ट फीचर सहित सुविधाओं के साथ पेश किए गए हैं।

तीन साल बाद भारत वापसी को तैयार, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर रहेगा फोकस

परिवहन विशेष न्यूज

फोर्ड मोटर कंपनी तीन साल बाद भारत वापसी को तैयार है। कंपनी का फोकस अब वैश्विक बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर रहेगा। कंपनी मांग और तकनीक में बदलाव के साथ अपनी रणनीति को समायोजित कर रही है। यह जानकारी कंपनी की रणनीति से परिचित एक व्यक्ति ने दी। बता दें कि लगातार घाटे के चलते फोर्ड मोटर ने सितंबर 2021 में भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया था। कंपनी को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इसके बाद फोर्ड ने भारतीय बाजार में अपना कारोबार बंद कर दिया।

फोर्ड के प्लांट बंद हुए फोर्ड ने फिगो, इकोस्पोर्ट, एंडेवर और एस्पायर जैसे मॉडलों के साथ आईसीई वाहन सेगमेंट में मजबूत जगह बनाई। इसने गुजरात के साणंद में एक विनिर्माण सुविधा संचालित की, जिसे 2022 में टाटा मोटर्स को बेच दिया गया। इसके अलावा चेन्नई के पास मराईमलाई नगर में एक और सुविधा थी, जिसे जुलाई 2022 में बंद कर दिया गया। हालांकि, अब जब वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार ईवी की ओर बढ़ रहा है, तो फोर्ड खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, 'फोर्ड को एहसास हो गया है कि 2025 भारत में ईवी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।₹ ₹पेट्रोल या डीजल वाहन बनाना अब व्यवहार्य उद्यम नहीं रह गया है, यही वजह है कि फोर्ड बैटरी मॉडल के लिए एक समर्पित असेंबली लाइन बनाने के लिए अपने चेन्नई प्लांट को फिर से तैयार कर रहा है। यह बदलाव फोर्ड के पारंपरिक ICE वाहनों पर पहले के फोकस से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।'

अपनी पुनः प्रवेश रणनीति के हिस्से के रूप में फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से निर्यात के लिए चेन्नई प्लांट को फिर से तैयार करने का इरादा व्यक्त किया गया है। यह घोषणा फोर्ड नेतृत्व द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से उनकी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान मुलाकात के बाद की गई। इस दौरान चेन्नई सुविधा में परिचालन फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई, जिसकी वार्षिक क्षमता 200,000 वाहन और 340,000 इंजन है।

सूत्र ने बताया कि फोर्ड का पहला कदम बैटरी पार्ट्स सहित ईवी घटकों के लिए एक मजबूत आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना होगा। सूत्र ने कहा, 'एक बार आपूर्तिकर्ता आधार तैयार हो जाने के बाद कंपनी अपनी चेन्नई सुविधा से इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू करेगी और उन्हें पास के बंदरगाहों के माध्यम से वैश्विक बाजारों में निर्यात करेगी। अगले चरण में फोर्ड इन वाहनों को घरेलू भारतीय बाजार में पेश करने की योजना बना रही है।'

फोर्ड मोटर इंडिया के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'निर्माण के प्रकार और अन्य विवरणों के बारे में आगे की जानकारी नियत समय में प्रदान की जाएगी और हम अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।'

फोर्ड की एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी की वैश्विक फोर्ड और विकास योजना के हिस्से के रूप में निर्यात के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चेन्नई सुविधा को फिर से तैयार किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में फोर्ड इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रुप के अध्यक्ष के हार्ट ने कहा, 'यह कदम भारत के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य नए वैश्विक बाजारों की सेवा के लिए तमिलनाडु की विनिर्माण विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।'

2021 में भारत से फोर्ड का बाहर निकलना एक बड़ी गलती के रूप में देखा गया क्योंकि देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ फोर्ड का वापस लौटने का फैसला एक सुविचारित कदम है जो कंपनी को लंबी अवधि में सफलता के लिए तैयार कर सकता है।

अर्जुन कपूर ने खरीदी ई-स्कूटर, बोले भीड़ में बचने के लिए ये है सबसे सही चीज़

परिवहन विशेष न्यूज

अर्जुन कपूर हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। 'इश्कजादे' और 'गुंडे' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अर्जुन कपूर बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में नाम कमा चुके अर्जुन कपूर लग्जरी कारों के काफी शौकीन हैं। उनके पास कई लाख और करोड़ों की कीमत की कारें हैं। इसी बीच उन्होंने मुंबई के विले पार्ले में अपने नए ई-स्कूटर की डिलीवरी ली है, जिसके साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने बुधवार 25 सितंबर को नई ई-स्कूटर खरीदी है। यह बाइक BGauss RUV 350 है। सामने आई तस्वीरों में अभिनेता नई ई-स्कूटर की डिलीवरी लेते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसके साथ शानदार पोज भी दे रहे हैं।

इतना ही नहीं वह इसे ड्राइव करके अपने घर भी ले जाते नजर आ रहे हैं। एक्टर के नए ई-स्कूटर को फूलों की माला से सजाया गया है। यह ग्रे कलर की बेहद स्टाइलिश बाइक है।

अर्जुन कपूर द्वारा खरीदी गई यह ई-स्कूटर कोई आम ई-स्कूटर नहीं है, बल्कि यह भारत की पहली आरयूवी फुल मेटल बॉडी के साथ आता है और इसे ऑफ-रोड आरामदायक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह क्रूज कंट्रोल मैकेनिज्म से लैस है और कंपनी के वेबसाइट के अनुसार ई-स्कूटर को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 35 मिनट का समय लगता है।

महिंद्रा थार रॉक्स कार 4x4 के सभी वेरिएंट का खुलासा; 3 अक्टूबर से बुकिंग शुरू, दशहरा से होगी डिलीवरी

परिवहन विशेष न्यूज

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड ने हाल में लॉन्च हुई Mahindra Thar Roxx 4x4 के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुसाला कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये है। महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 वेरिएंट की कीमत 4x2 वेरिएंट से 1.8 लाख रुपये से 2 लाख रुपये ज्यादा है। भारत में इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 5-डोर और मारुति जिम्नी से है।

नई दिल्ली। महिंद्रा थार रॉक्स के 4x4 वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया गया है। इसके 4x4 वेरिएंट की शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये है। इसे इस साल 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं कि 4x4 वेरिएंट की कीमतों के बारे में और यह किन फीचर्स के साथ आती हैं।

Mahindra Thar Roxx 4x4: कीमत

- MX5 डीजल 4x4 MT वेरिएंट की कीमत 18.79 लाख रुपये है।
- AX5L डीजल 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये है।
- AX7L डीजल 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 20.49 लाख रुपये है।
- AX7L डीजल 4x4 MT वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये है।

Mahindra Thar Roxx 4x4: स्पेसिफिकेशन

महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 को 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था। इसका मैनुअल वेरिएंट वाला इंजन 150 bhp और 330 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसके 4x4 ऑटोमैटिक वेरिएंट 172 bhp और 370 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें महिंद्रा का 4XPLOR सिस्टम दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और टेरेन मोड मिलते हैं।

इसके साथ ही महिंद्रा थार रॉक्स में क्रॉलस्मार्ट फीचर दिया गया है, जो ड्राइवर को एक्सीलेटर पैडल पर पैर रखे बिना स्थिर कम स्पीड बनाए रखने की परमिशन देता है। इसके अलावा, नया इंटेलीटर्न फीचर दिया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी फायदेमंद रहने वाला है।

इस दिन से शुरू होगी बुकिंग

महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 की बुकिंग 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने जा रही है। इसे लेने की चाहत रखने वाले ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं। वहीं, इसकी डिलीवरी 12 अक्टूबर, 2024 को दशहरा के दिन से शुरू होगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 5-डोर और मारुति जिम्नी से है।

प्लग एन राइड मोटर्स और ट्राईव्हील ने वित्तीय भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्लग एन राइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्राईव्हील ने रणनीतिक वित्तीय साझेदारी स्थापित करने के लिए नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्लग एन राइड मोटर्स के संस्थापक और सीईओ जफर इकबाल और ट्राईव्हील के संस्थापक सचिन तलुजा के बीच मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को समझौते को औपचारिक रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य ईवी खरीदारों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ाना है।

यह भागीदारी प्लग एन राइड इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक सहज वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगी, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए संधारणीय गतिशीलता में बदलाव करना आसान हो जाएगा। यह सहयोग आकर्षक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन करने के लिए दोनों कंपनियों की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

इस अवसर पर बोलते हुए ज़फ़र इक्बाल ने कहा, "ट्राइव्हील के साथ यह वित्तीय साझेदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक दर्शकों के लिए किफ़ायती और सुलभ बनाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस साझेदारी के साथ हम अपने ग्राहकों को लचीले वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिससे उनका समग्र खरीद अनुभव बेहतर होगा।

सचिन तलुजा ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, 'हम प्लग एन राइड मोटर्स के साथ हाथ मिलाकर उत्साहित हैं। हमारा सहयोग न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगा बल्कि अधिक लोगों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो एक स्थायी भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।'

यह समझौता ज्ञापन भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्लग एन राइड और ट्राइव्हील दोनों की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

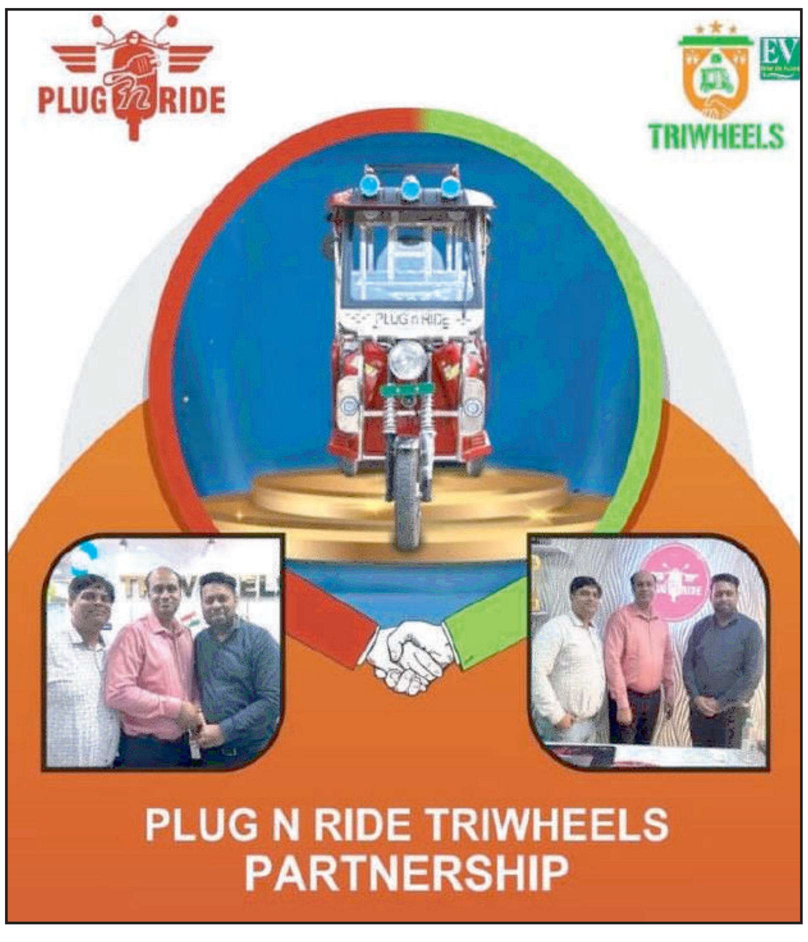

टाटा नेक्सॉन बनी टर्बो इंजन वाली देश की पहली CNG गाड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स की Tata Nexon CNG को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह भारत की पहली CNG गाड़ी है जिसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगाया गया है। यह अब पैनोरमिक सनरूफ भी है। इसे 8 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके सभी वेरिएंट की कीमत और फीचर्स के बारे में।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने भारत में Nexon CNG को लॉन्च कर दिया है। इसे कुल आठ वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.99 लाख रुपये है। सीएनजी वाले में नए फीचर्स के साथ ही टर्बो इंजन भी दिया गया है। आइए जानते हैं Tata Nexon CNG के सभी वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं और उनकी कीमत कितनी है।

Tata Nexon CNG: इंजन

टाटा नेक्सन सीएनजी वेरिएंट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 100hp और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें ट्विन-टैंक सेटअप दिया गया है।

वहीं, यह भारत में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली पहली सीएनजी गाड़ी है।

Tata Nexon CNG: वेरिएंट

इसे आठ वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो स्मार्ट (O), स्मार्ट +, स्मार्ट +S, प्योर, प्योर S, क्रिएटिव, क्रिएटिव + और फियरलेस + PS है।

Tata Nexon CNG ट्रिम-वाइज फीचर लिस्ट

Tata Nexon CNG Smart
कीमत - 8.99 लाख रुपये
6 एयरबैग
EPS
DRLs के साथ LED हेडलैंप
LED टेल-लैंप
इलुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील लोगो
फ्रंट पावर विंडो
हिल-होल्ड कंट्रोल

Tata Nexon CNG Smart +
कीमत - 9.69 लाख रुपये
स्मार्ट से ज्यादा फीचर्स
7.0-इंच टचस्क्रीन
वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले
शार्क फिन एंटीना
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल
सभी पावर विंडो
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs

Tata Nexon CNG Smart + S
कीमत - 9.99 लाख रुपये
स्मार्ट+ से ज्यादा फीचर्स
ऑटो हेडलैंप
इलेक्ट्रिक सनरूफ
रेन सेंसिंग वाइपर

समानता के लिए महिलाओं की लड़ाई का विस्तार डिजिटल क्षेत्र तक हो गया है

विजय गर्ग

आज की दुनिया में, महिलाएं न केवल सार्वजनिक रूप से बल्कि डिजिटल स्थानों पर भी अपने अधिकारों का दावा कर रही हैं, और जीवन के सभी पहलुओं में समानता की मांग कर रही हैं। महिलाएं मूल ₹कंप्यूटर₹ थीं। पुराने ज़माने में, 1800 के दशक के उत्तरार्ध में, ये महिला कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में काम करती थीं, जो कठिन गणनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को मैन्युअल रूप से तैयार करती थीं, यह कार्य अक्सर पुरुष वैज्ञानिकों के लिए बहुत मामूली समझा जाता था। तब और आज के बीच, न केवल एसटीईएम अनुसंधान की रीढ़ के रूप में देखी जाने वाली हमारी भूमिका कम हो गई है, बल्कि हमने आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में एक समान हिस्सेदारी भी खो दी है। आज, हमारे आसपास की महिलाएं डिजिटल क्षेत्र सहित जीवन के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से समानता की मांग करती हैं। अनगिनत महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया भर में बदलाव को प्रेरित किया है और डिजिटल स्पेस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। हालाँकि, ऐतिहासिक हाशिए के अवशेष हमारे आभासी स्थानों में घुस गए हैं और महिलाओं के लिए डिजिटल इक्विटी हासिल करने के रास्ते में बाधा बन गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, सक्रिय रूप से चुप करा दिया जाता है और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। हाल ही में, मैंने वाइटल वॉयस ग्लोबल एक्शन समिट में भाग लेने के लिए वारसॉ का दौरा किया, जो अधिकारों और लोकतंत्र के लिए महिलाओं पर केंद्रित था, जहां मैंने विभिन्न देशों और कार्य क्षेत्रों - सक्रियता, नीति और राजनीति में महिलाओं की आवाज़ों का एक सम्मिलन देखा। इन आवाज़ों का अभिसरण महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की वकालत करने और इस बात पर प्रकाश डालने तक सीमित नहीं था कि महिलाएं मजबूत लोकतंत्रों के लिए कैसे लड़ रही हैं क्योंकि उनके अधिकार लोकतांत्रिक देशों का आधार हैं; बल्कि इस बात पर भी कि कैसे महिलाओं की तकनीक तक असमान पहुंच है, कैसे तकनीक महिलाओं को सक्रिय रूप से अदृश्य और चुप कराकर लोकतंत्र का एक विकृत विचार बनाती है, कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम विभिन्न प्लेटफार्मों पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान नहीं कर रहे हैं जो ₹स्वतंत्र भाषण के विचार को बढ़ावा देते हैं₹ और कैसे उसी ₹स्वतंत्र भाषण₹ का उपयोग दबंगों और निरंकुश लोगों द्वारा एक उपकरण के रूप में किया जाता है और ट्रोलिंग के खिलाफ कोई निश्चित कार्रवाई नहीं की जाती है। इन चुनौतियों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है, और सभी देश अधिकारों और लोकतंत्र के विचारों के माध्यम से इनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में सबसे बड़ी बाधा मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच की कमी रही है। नवीनतम एनएफएचएस सर्वेक्षण के अनुसार, 15 से 49 वर्ष के बीच की हमारी महिला आबादी में से केवल एक-तिहाई ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है, जबकि इसी आयु वर्ग में आधे से अधिक पुरुष आबादी ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। डिजिटल विभाजन महिलाओं की उम्र में वृद्धि, उनके परिवार की आय में कमी, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए जैसे कारकों के साथ बिगड़ता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के पास अक्सर मोबाइल फोन का स्वामित्व नहीं होता है, उनके उपकरण परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं या उनकी निगरानी की जाती है, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी में और बाधा आती है। जो महिलाएं इन पहुंच बाधाओं को दूर करने में सफल हो जाती हैं, उनके लिए अगली चुनौती उभरती है - साइबर अपराधों की चिंताजनक रूप से उच्च दर जिसमें धमकियां, हिंसा, अश्लील साहित्य, पीछा करना और बहुत कुछ शामिल हैं। यह एक दोधारी तलवार है, भारतीय अदालतें कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन बदमाशी के अन्य रूपों के मामलों को भौतिक दुनिया में किए गए अपराधों की तुलना में कम गंभीरता से लेती हैं। साथ में, दोनों पक्ष एक भयावह प्रभाव पैदा करते हैं और महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुखर होने और ऐसी भूमिकाएँ निभाने से रोकते हैं जो उन्हें राजनीति सहित डिजिटल सुर्खियों में लाती हैं। इसके अलावा, भारतीय महिला राजनेताओं का सामना करना पड़ता हैअमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में काफी अधिक ट्रोलिंग हो रही है, अल्पसंख्यक समूहों के लोग और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले और पुरुष राजनीतिक नेताओं को घृणा अभियानों के अधिक क्रूर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बुल्ली बाई और सुल्ली डील घोटालों को महिलाओं को चुप कराने के लिए लक्षित धमकियों और धमकाने की गंभीरता की याद दिलाने के रूप में काम करना चाहिए - एक ऐसा मामला जो लंबे समय तक केंद्र सरकार द्वारा अनसुलझा रहा। यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के तहत मुंबई पुलिस थी, जिसने मामले को सुलझाया था और पीड़ितों की अथक उम्मीदों के बाद आरोपियों को सजा दी थी कि केंद्र सरकार कदम उठाएगी और इसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ उठाएगी। . तीसरी बाधा अजीब और लगातार विकसित होने वाली है: सोशल मीडिया एल्गोरिदम। अपनी कथित प्रगतिशीलता के बावजूद, यह एल्गोरिदम लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों का प्रचार करता प्रतीत होता है जिन्हें हम समाज से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियाँ उपयोगकर्ता अनुभवों को बेहतर बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित बनाने के वादे के साथ आईं। हालाँकि, ये वादे समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित प्रतीत होते हैं। मानवीय पूर्वाग्रह एआई पूर्वाग्रहों में बदल गए हैं और लिंगवादी और नस्लवादी प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, समान संदर्भों में पुरुषों और महिलाओं की तस्वीरों को एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा अलग-अलग तरीके से आंका जाता है। स्पोर्ट्सवियर या अधोवस्त्र में महिलाओं की छवियों को पुरुषों की तुलनीय तस्वीरों की तुलना में एआई के 'रेसी' पैमाने पर बहुत अधिक अंक दिए गए हैं। अवतार-जनरेटिंग एआई ऐप्स ने इसी तरह के पैटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसमें एआई पुरुषों को अंतरिक्ष यात्री, योद्धा, या संगीत एल्बम कवर पर देखता है और महिलाओं के अवतार ज्यादातर नग्न और स्वयं के अत्यधिक कामुक संस्करण होते हैं। एआई का पूर्वाग्रह तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब महिला चेहरों को पुरुष का लेबल दिया जाता है और अवतार अधिक मुखर दिखने वाले और पूरी तरह से कपड़े पहने हुए पात्रों में बदल जाते हैं। एल्गोरिदम बाधा के साथ समस्या व्यक्तिगत छवियों से परे फैली हुई है। इन उपकरणों के पीछे की तकनीक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, फिर भी इसका उपयोग हमारे सोशल मीडिया फ़ीड में आने वाली चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एआई किसी छवि को कैसे 'रेसी' रेटिंग देता है, इसे निर्माता को पता चले बिना दर्शकों तक पहुंचने से रोका जाता है। राजनीतिक संदेशों वाले पोस्ट पर भी इसी प्रकार की सेंसरशिप देखी गई है। अलग-अलग उदाहरणों में, एल्गोरिदम ने स्त्री-द्वेषी सामग्री को तेजी से बढ़ाया है, विशेष रूप से युवा दर्शकों के लिए, महिलाओं पर निर्देशित क्रोध और दोष पर बढ़ी हुई सामग्री के साथ, एल्गोरिदम के साथ महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करने वाले स्पष्ट मुद्दों का संकेत मिलता है। दुर्भाग्य से यह महिलाओं पर छोड़ दिया गया है कि वे एल्गोरिदम को मात देने और इन पूर्वाग्रहों से लड़ने के लिए रचनात्मक तरीके खोजें क्योंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यहां तक कि 20 सबसे बड़ी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी, महिलाओं की संख्या 33% कार्यबल है और 2022 तक केवल 25% ही नेतृत्व पदों पर हैं। नीति और प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ भारत को डिजिटल इक्विटी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर देती हैं। दुनिया में एसटीईएम स्नातकों की सबसे अधिक संख्या के साथ - जिनमें से 40% महिलाएं हैं - महिला आबादी का एक बड़ा हिस्सा भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल किया जा सकता है। फिर भी, इन संख्याओं के बावजूद, तकनीकी कार्यबल में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम है। जैसा कि भारत खुद को एसटीईएम में एक वैश्विक नेता के रूप में रखता है, लक्षित नीतियों के माध्यम से महिला प्रतिभा के अपने अप्रयुक्त पूल का उपयोग करके व्यवस्थित परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे दुनिया भर में महिलाओं के लिए डिजिटल और भौतिक इक्विटी दोनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी नीतियों को इसे प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है और उन्हें सुविधाप्रदाता बनना चाहिएकार्यस्थलों में अधिक महिलाओं को शामिल करना, महिला तकनीकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उद्योगों को अधिक समानता लाने के लिए प्रेरित करना, ऑनलाइन उत्पीड़न से सख्ती से निपटना और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना, जिसके परिणामस्वरूप भारत को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाना है। अनुसरण करना। तकनीकी और वैज्ञानिक टीमों में, विशेष रूप से विविध पृष्ठभूमि से, अधिक लड़कियों और महिलाओं को शामिल करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का विकास पहुंच, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन दुरुपयोग के आसपास महिलाओं की अनूठी चुनौतियों का समाधान करता है। महिलाओं को न केवल तकनीकी भूमिकाओं के लिए बल्कि नेतृत्व पदों के लिए भी प्रशिक्षित करने से उन्हें तकनीक से संबंधित नीतियों और निर्णयों को आकार देने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः सुरक्षित, अधिक समावेशी डिजिटल स्थान प्राप्त होंगे।

आज की दुनिया में, महिलाएं न केवल सार्वजनिक रूप से बल्कि डिजिटल स्थानों पर भी अपने अधिकारों का दावा कर रही हैं, और जीवन के सभी पहलुओं में समानता की मांग कर रही हैं। महिलाएं मूल ₹कंप्यूटर₹ थीं। पुराने जमाने में, 1800 के दशक के उत्तरार्ध में, ये महिला कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में काम करती थीं, जो कठिन गणनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को मैन्युअल रूप से तैयार करती थीं, यह कार्य अक्सर पुरुष वैज्ञानिकों के लिए बहुत मामूली समझा जाता था।

संपादकीय

मिलावट ही 'सत्य' है

भारत में मिलावट और भ्रष्टाचार कोई नई प्रवृत्तियां नहीं हैं। खाद्य पदार्थ ही नहीं, हमारी हवा और पानी भी प्रदूषित हैं। खाने की चीजों में इनसान की उंगली, छिपकली, सांप के टुकड़े पाए जाने की असंख्य घटनाएं सामने आती रही हैं। कानून तो है, लेकिन खाद्य निरीक्षकों की निगरानी और व्यवस्था गायब और लचर है। उनके अपने 'हफ्ते' या 'महीना' बंधे हैं। दूध में पानी या सोडा मिलाया जाता है, खोया भी मिलावटी और रासायनिक है, देशी घी के नाम पर हम 'बाबाओं' के दावों का अनुसरण करते हैं, लिहाजा भ्रम में जीते हैं कि हम विशुद्ध देशी घी खा रहे हैं। अब कुछ भी शुद्ध मिलना असंभव है, क्योंकि यह मोटे मुनाफे और मिलावट का 'कलियुग' है। आत्मा से हम बेईमान और भ्रष्ट हैं। मुनाफे और मिलावट के लिए कोई भी ठेकेदार भगवान तक को ठग सकता है। आस्था और श्रद्धा को खंडित और अपमानित कर सकते हैं। बेशक मंत्रोच्चारण के जरिए तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण कर लिया गया हो, यह कर्मकांड का आत्मसंतोष हो सकता है, लेकिन करोड़ों भक्तों ने 'प्रसादम् लड्डू' का जो ग्रहण किया है, प्रसाद को अन्य भक्तों में भी बांटा है, उनका शुद्धिकरण कैसे संभव है? तिरुपति मंदिर में औसतन 3.5 लाख लड्डू रोजाना भक्तों के हाथों में जाते हैं। प्रसाद के इन लड्डुओं से तिरुपति मंदिर को 500-600 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। प्रसाद, मंदिर और कमाई बिल्कुल विरोधाभासी हैं। देश में हिंदू या गैर-हिंदुओं के हजारों मंदिर ऐसी ही 'दुकानदारी' चला रहे हैं। दुकान खोलोगे, तो मिलावटी वस्तुएं भी आएंगी और उन्हें विक्रेता का धर्म निभाना पड़ेगा! अब तिरुपति प्रकरण के बाद मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों में भी जांच का मुद्दा उठाया गया है। वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर में बंटने वाले प्रसाद की भी जांच की जाएगी। किसी मंदिर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है कि भक्तगण अपने घरों से प्रसाद बनाकर लाएं और मंदिर में भगवान को भोग लगाएं। अथवा ड्राई फ्रूट्स प्रभु के चरणों में चढ़ाए जा सकते हैं। दरअसल बुनियादी मुद्दा और संकट मिलावट और बदनीयत का है।

आखिर भक्तगण विशुद्ध दूध और घी कहां से लाएंगे? लिहाजा घर में बना प्रसाद भी 'अशुद्ध' और मिलावटी हो सकता है। यही नहीं, स्कूलों में बच्चों को जो 'दोपहर का खाना' दिया जाता है, वह भी मिलावटी, प्रदूषित होता रहा है, क्योंकि बच्चे वह खाना खाकर बीमार पड़ते रहे हैं। मौतें भी हुई हैं। उस खाने में भी छिपकली और सांप पाए जाते रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? देश में पूजा-स्थलों और मंदिरों में लोगों की गहरी आस्था और विश्वास होता है। मंदिर के जरिए आम भक्त भगवान से साक्षात्कार महसूस करना चाहता है। अब आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के जरिए यह मुद्दा बेपर्दा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को 'खलनायक' करार दिया जा रहा है। बेशक राज्य सरकार ने सभी पुराने ठेके, सप्लाई आदि को रद्द कर दिया है। विशेष जांच दल भी गठित कर दिया गया है, लेकिन अंततः यह सियासी खुन्नस का मामला भी साबित हो सकता है। इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है, जबकि बुनियादी मुद्दा मंदिरों में जाने वाले भक्त की आस्था और मिलावट के जरिए उसकी आत्मा को अपवित्र करने की हरकतों का है। अभी लड्डू प्रसादम् की वैज्ञानिक जांच सामने आनी है। देश की सबसे बड़ी और सार्थक प्रयोगशाला हैदराबाद में है, जबकि पूरी चिल्ल-पौं की आधार गुजरात की लैब की रपट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुराष्ट्रीय अध्ययन के संदर्भ में भारत के 17 शहरों से भी कुछ नमूने लिए।

निष्कर्ष यह रहा कि 14 फीसदी नमूनों में उच्च स्तर की धातु मिलाई गई थी। बेशक दूध के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन ने विकास की बुलंदियां छुई हैं, लेकिन आधा से ज्यादा क्षेत्र अब भी असंगठित है। इसमें घी बनाने वाली इकाइयां भी हैं। संसद को यह बताया गया था कि 3 में से 2 भारतीय जो दूध का उपयोग करते हैं, उसमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया अथवा पेंट आदि मिले होते हैं। इतने व्यापक स्तर पर मिलावट को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

सोशल मीडिया आयु सीमा: क्या बच्चों पर प्रतिबंध लगाना काफी

हालाँकि आयु सीमा निर्धारित करना एक सीधा समाधान प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना कहीं अधिक जटिल चुनौती है बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रस्ताव ने वैश्विक बहस छेड़ दी है कि युवाओं को इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचाया जाए। सरकार द्वारा 14 से 16 वर्ष के बीच आयु सीमा का सुझाव देने के साथ, इरादा स्पष्ट है: बच्चों को अत्यधिक स्क्रीन समय, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और अवास्तविक सामाजिक तुलनाओं से जुड़े सामाजिक नुकसान से बचाना। लेकिन क्या पूर्ण प्रतिबंध इसका उत्तर है? क्या हम इस कदम के प्रभावी होने की उम्मीद कर सकते हैं, या हम समस्या को केवल कालीन के नीचे दबा रहे हैं? सैद्धांतिक रूप से, सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आयु सीमा निर्धारित करना एक सीधा समाधान जैसा प्रतीत होता है। हालाँकि, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। सोशल मीडिया पर आयु सीमा लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक उपयोगकर्ताओं की उम्र को विश्वसनीय रूप से सत्यापित करने में होने वाली कठिनाई है। अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म पर पहले से ही न्यूनतम आयु आवश्यकताएँ हैं। फिर भी, हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे इन प्लेटफार्मों पर सक्रिय हैं, अक्सर पंजीकरण के दौरान गलत जन्मतिथि दर्ज करके आयु प्रतिबंधों को दरकिनार कर देते हैं। यह एक खामी है जिसका फायदा उठाना बहुत आसान है, और एक मजबूत सत्यापन प्रणाली के बिना, आयु सीमा बढ़ाना कोई समाधान नहीं हो सकता है। कुछ प्लेटफार्मों ने आईडी सत्यापन या यहां तक कि चेहरे की पहचान जैसे उपायों को पेश करने का प्रयास किया है, लेकिन ये समाधान अपनी चिंताओं के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, YouTube किड्स को माता-पिता की पहचान सत्यापित करने के लिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी की आवश्यकता होती है। नेक इरादे से होने के बावजूद, यह तरीका गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा करता है और फुलप्रूफ से कोसों दूर है। इसके अलावा, तकनीक-प्रेमी बच्चे अक्सर वीपीएन का उपयोग करके ऐसे उपायों को मात दे देते हैं। बच्चों की पहुंच पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने की पुख्ता व्यवस्था के बिना उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना सामने के दरवाजे पर ताला लगाने और पीछे के दरवाजे को खुला छोड़ने जैसा है। जब सोशल मीडिया और बच्चों पर इसके प्रभाव पर चर्चा होती है, तो माता-पिता की निगरानी अनिवार्य रूप से सामने आती है। माता-पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों की इन प्लेटफार्मों तक पहुंच की निगरानी और नियंत्रण करें, लेकिन क्या वे इस हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? उत्तर, दुर्भाग्य से, नहीं है। यहां तक कि सबसे मेहनती माता-पिता से भी अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि के हर मिनट की निगरानी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पर एक नेक इरादे वाला प्रतिबंध माता-पिता को सुरक्षा की झूठी भावना दे सकता है, लेकिन यह इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि बच्चे इन प्लेटफार्मों तक पहुंचने के तरीके ढूंढ लेंगे। यदि हम उन्हें विनियमित, मुख्यधारा के प्लेटफार्मों से दूर कर देते हैं, तो वे इंटरनेट के अंधेरे, अनियमित कोनों में शरण ले सकते हैं - ऐसे स्थान जहां साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री के संपर्क और यहां तक कि शिकारी व्यवहार के जोखिम और भी अधिक हैं। निस्संदेह, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यह बच्चों को जीवन के अवास्तविक चित्रणों से अवगत कराता है, जिससे उनमें चिंता, अवसाद और दूसरों से बराबरी करने की निरंतर आवश्यकता पैदा होती है। दूसरी ओर, यह युवाओं को जुड़ने, खुद को अभिव्यक्त करने और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए जगह प्रदान करता है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से जहरीले पहलू दूर हो सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें इन मूल्यवान अवसरों से वंचित भी किया जा सकता है। माता-पिता और शिक्षक के रूप में, हमारी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। प्रतिबंध लगाने की दिशा में जल्दबाजी करने के बजाय, बच्चों को ऑनलाइन दुनिया को जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक विवेकपूर्ण हो सकता है। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, और माता-पिता के बीच खुली बातचीतबच्चे युवा दिमागों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने में काफी मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया को पराजित होने वाले दुश्मन के रूप में देखने के बजाय, हमें इसे एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए जिसे सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। आयु प्रतिबंध, जब ठीक से लागू किए जाते हैं, तो युवा उपयोगकर्ताओं को बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन समग्र समाधान के बिना - बेहतर माता-पिता के समर्थन से लेकर अधिक विश्वसनीय आयु सत्यापन विधियों तक - उनकी प्रभावशीलता सीमित होगी।

संचार के जाल में में उलझा बचपन

विजय गर्ग

बच्चों की सोशल मीडिया पर व्यस्तता, आनलाइन गेमिंग और इंटरनेट की लत को लेकर दुनिया के कई देशों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की कि सोशल मीडिया के उपयोग की उम्र तय होनी चाहिए। आस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में लोग आनलाइन व्यस्त रहते हैं और बारह से सत्रह वर्ष के लगभग पचहत्तर फीसद बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चौदह पंद्रह वर्ष की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया के बजाय खेल के मैदानों में खेल का आनंद लेते देखना चाहते हैं।

भारत में भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि बच्चों को अपने कंप्यूटर-मोबाइल से दूर रह कर, वास्तविक जीवन के अनुभव लेने चाहिए। बच्चों को अनजान लोगों से आनलाइन जुड़ने की जगह, आसपास के मोहल्ले, बस्ती गांव वास्तविक लोगों से मिलना-जुलना चाहिए, यह सामाजिक और भाषाई विकास सहायक होगा। तमिलनाडु में लगभग बीस फीसद विद्यार्थी आनलाइन गेम की लत से ग्रस्त हैं। वहाँ हुए एक अध्ययन में दो लाख स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को शामिल किया कया गया था। इसी तरह राजस्थान के जयपुर में मनोचिकित्सालय की तरफ से बच्चों में इंटरनेट की लत को लेकर उनमें होने वाले व्यावहारिक और भावनात्मक बदलाव पर शोध शुरू हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी अभिभावकों, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया है कि लंबी अवधि तक बच्चों द्वारा कंप्यूटर-इंटरनेट के उपयोग और देर तक आनलाइन गेम खेलने मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियां उभर रही हैं।

कारण दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में स्नायविक और सिरदर्द की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, पीठ दर्द की समस्या बढ़ रही है। बारह से अठारह वर्ष के बच्चों में अत्यधिक 'स्क्रीन टाइम' के चलते बेचैनी, अकेलापन, बात-बात पर गुस्सा, अनिद्रा और पढ़ाई में मन न लगने जैसे लक्षण दिखते हैं तो यह चिंता की बात है। अनुमान है कि कोई बच्चा अगर एक घंटा फोन इस्तेमाल करता है तो उसकी नींद सोलह मिनट कम हो जाती है। जब नींद पूरी नहीं होगी, तो एकाग्रता का अभाव होगा और व्यवहार तथा भाषा में उग्रता आ सकती है। कोरोना आनलाइन 'के बाद से स्कूली छात्रों में एकाग्रता की समस्या कई जगह देखी गई है।

'यूनेस्को' ने पहले ही, सीखने की गुणवत्ता की चिंता, एकाग्रता की समस्या, कक्षा में अवरोध, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के चलते दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्ट फोन को प्रतिबंधित करने की अपील की थी, लेकिन अभी उसका असर एक चौथाई देशों में ही हुआ है। ब्राजील की एक संस्था ने 2017-2018 में एक अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि तीन घंटे से अधिक समय तक फोन का उपयोग करना बच्चों के लिए खतरनाक होता है। अधिक फोन इस्तेमाल करने वाले चौदह से अठारह

वर्ष आयु वर्ग के 2628 छात्रों पर हुए इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि 39 फीसद लड़के और 55 फीसद लड़कियां 'थोरासिस स्पाइन पेन' (टीएसपी) से ग्रस्त थीं। इस वजह से गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। भारत सहित दूसरे देशों में अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों के शारिरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उन्हें खेल के मैदान पर भेजें।

तकनीकी हमारे जीवन को कुछ सुगमता दे रही है, लेकिन उससे बढ़ती परेशानियां अब घरों के भीतर दिख रही है। आज के बच्चों की बाहरी दुनिया मुख्य रूप से सोशल मीडिया के आसपास सिमटती जा रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के 'लाइक' से वे खुश और दुखी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वे दिखाना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी शानदार है और वे किसी की परवाह नहीं करते हैं। बच्चों में कुछ भी मांगने का चलन बढ़ रहा है, भले ही उस सामान की कोई बहुत जरूरत न हो। कुछ भी मांगते रहने में केवल बच्चों का अपना दोष नहीं है। बच्चों के लिए सामान बनाने वाली कंपनियां अब बच्चों को अपना 'कर्मचारी/ ब्रांड एंबेसडर रखती और उनके जरिए सोशल मीडिया पर 'मार्केटिंग' कराती हैं। मनोवैज्ञानिकों की मदद से बच्चों के लिए ऐसी 'मार्केटिंग' रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें अभिभावक बीच न आएं और सीधे बच्चों तक 'प्रोडक्ट' या उत्पाद दिख जाए। सुसान लिन ने ने एक पुस्तक लिखी है- 'हू इज रेजिंग द किड्स ?' उसमें बताया गया है कि कैसे तकनीकी के साथ बाजारी संस्कृति और उपभोक्तावाद बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है। लिन मानती हैं कि पैदा होते ही बच्चा मीडिया, एप्प और खिलौने बनाने वाली कंपनियों के लिए एक आकर्षक शिकार बन रहा है। इस किताब में रसेल बैंक का उल्लेख है। रसेल बैंक ने ने बाजार की अधिकाधिक मुनाफे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 'यह बाजार वाला समाज अपने बच्चों को उपभोक्ता में बकहा है बदल देता है, जिसमें बच्चे सिर्फ मांगते हैं। बच्चों और उनके माता-पिता को यह बाजार वह बेचेगा जो बच्चे मांग रहे हैं, न कि वह चीज, जिसकी बच्चों को वास्तव में जरूरत है।' मगर इन समस्याओं को चिह्नित कर लेने के बाद भी समाधान क्या है ? बड़ी चुनौती यह है कि अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय निकालना असंभव लगता है। अभिभावक अपनी भूमिका ही नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चों के बाजार तथा दूसरों के भरोसे पल जाने की कल्पना कर रहे हैं।

आनलाइन लत के कारण बच्चों की सामाजिक परिधि छोटी होती जा है। उनमें शरीरिक श्रम से। श्रम से पलायन का भाव दिख रहा है। भागदौड़ की जिंदगी में अभिभावक अपने बच्चों से सुबह-शाम भी नहीं मिल पाते हैं। आखिर, माता-पिता की जगह टीवी- कंप्यूटर से बच्चे नैतिकता सीख रहे हैं।बच्चे इंटरनेट के जरिए किसके संपर्क में हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभिभावकों के पास यह जानने-सुनने का समय ही नहीं है। तकनीकी विकास से बढ़ता बाजार हमें कहां ले जा रहा है?

आस्ट्रेलिया में 2022 में 'ई सेफ्टी' लेकर हुए एक सर्वे में वयस्कों अपने आनलाइन के अनुभव साझा किए थे उसमें अवांछित सामग्री भेजने से लेकर बिना अनुमति उनके खाते तक पहुंचने की चिंता सामने आई थी। इसीलिए बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की बात आस्ट्रेलिया में उठी है। इसके पहले यूरोपीय संघ ने भी ऐसा प्रयास किया था कि बच्चे एक निर्धारित उम्र से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, मगर बच्चों के आनलाइन अधिकारों की वकालत करने वाले संगठनों की आलोचना से यूरोपीय संघ सोशल मीडिया उपयोग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं लागू करवा पाया। अब सवाल है कि क्या अभिभावक अपने स्तर पर बच्चों के 'स्क्रीन टाइम' को कम करने की पहल कर सकते हैं ?मलोट

जीडीपी ग्रोथ के मामले में सबसे रहेगा भारत, क्या आम लोगों को भी मिलेगा फायदा?

परिवहन विशेष न्यूज

दुनिया की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार रहेगा। वहीं एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बेहतर कृषि उत्पादन और अधिक सरकारी खर्च से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या इससे आम जनता को भी फायदा होगा?

नई दिल्ली। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि मजबूत जीडीपी वृद्धि और सकारात्मक निवेश भावना से प्रेरित होकर भारत 2030 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

ब्रोकरेज कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की आय में स्थिरता आनी शुरू हो गई है, क्योंकि देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी लचीला बना हुआ है। पिछले पांच सालों में निफ्टी की कुल आय वृद्धि और बाजार पूंजीकरण दोनों ने 18 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की है।

कितनी रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बैंक ने कहा कि बेहतर कृषि उत्पादन और अधिक सरकारी खर्च से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सितंबर के अपने एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) में एडीबी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में निर्यात पहले के अनुमान से अधिक रहेगा। इसमें बड़ी भागीदारी सर्विसेज की होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कृषि सुधारों से ग्रामीण खर्च बढ़ेगा, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के प्रभावों का पूरक होगा।

हालांकि अगले वित्त वर्ष में निर्यात वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रहेगी। एडीबी ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। दोनों ही वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान अप्रैल, 2024 में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार हैं। पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

अच्छे मानसून का दिखेगा असर

एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर धीमी होकर 6.7 प्रतिशत पर आ गई है, लेकिन कृषि में सुधार और उद्योग व सेवाओं के लिए काफी हद तक मजबूत संभावनाओं के साथ आने वाली तिमाहियों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक मानसून से कृषि में मजबूत वृद्धि होगी, जिससे चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आर्थिकी बढ़ेगी। मजबूत कृषि और पहले से ही मजबूत शहरी खपत से ग्रामीण खपत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निजी खपत में सुधार होने की उम्मीद है। निजी निवेश के लिए संभावनाएं आशावादी हैं, लेकिन सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि अगले वित्त वर्ष में धीमी हो जाएगी।

30 लाख कमाई क्लब में जुड़ेंगे 11.3 करोड़ परिवार

भारत की आर्थिक तरक्की से जनता की जिंदगी भी गुलजार होगी। वित्त वर्ष 2031 तक 11.3 करोड़ नए ऐसे भारतीय परिवार होंगे, जिनकी वार्षिक आय 30 लाख रुपये से अधिक होगी। यू ग्रो कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच से 10 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग के परिवारों की संख्या में 28.3 करोड़ की वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त डालर के संदर्भ में देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2029 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे भारतीय परिवारों द्वारा खपत और खर्च को और बढ़ावा मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि व्यवसायों के लिए नए अवसर भी पैदा करेगी क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग बढ़ती है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ भारतीय करेंसी भी चमक उठा, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे चढ़ा रुपया

Dollar vs Rupee शेयर बाजार के दोनों सूचकांक अपने ऑल-टाइम हाई पर बंद हुआ। बाजार में जारी तेजी का असर भारतीय करेंसी पर भी पड़ा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे चढ़कर खुला। सुबह के कारोबार में भी रुपया तेजी के साथ खुला था। जहां एक तरफ रुपये में तेजी जारी है तो वहीं ग्रीनबैक में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

नई दिल्ली। आज भारतीय शेयर बाजार के दोनों सूचकांक अपने नए उच्चतम स्तर पर खुला। भारतीय बाजार में जारी तेजी ने रुपये को बढ़त हासिल करने में मदद की है। इसके अलावा यूएस फेड के फैसले के बाद से रुपया मजबूत प्रदर्शन कर रहा है।

फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार फॉरेन फंड आउटफ्लो ने भारतीय करेंसी में तेज बढ़त को सीमित कर दिया।

कितने पैसे चढ़ा रुपया

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा पर रुपयाअमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.59 पर थोड़ी मजबूत खुली। यह सत्र के दौरान 12 पैसे बढ़कर 83.51 पर पहुंच गया।
हालांकि, बाद में भारतीय करेंसी ने अपना अधिकांश लाभ गंवा दिया और 83.60 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद से 3 पैसे अधिक है।

पिछले सत्र यानी मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 83.63 पर बंद हुआ।

डॉलर इंडेक्स का हाल

इस बीच डॉलर इंडेक्स 0.55 प्रतिशत बढ़कर 100.52 पर था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.25 प्रतिशत बढ़कर 74.98 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने 2,784.14 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

शेयर बाजार का हाल

आज सेंसेक्स 255.83 अंक चढ़कर 85,169.87 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 63.75 अंक चढ़कर 26,004.15 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

5 अक्टूबर के बाद घटेंगे पेट्रोल और डीजल के भाव? CLSA की रिपोर्ट से बड़ी राहत का संकेत

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले महीने पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा था कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं तो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने पर विचार कर सकती हैं। सीएलएसए के मुताबिक महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य है। वहां के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुआई वाला गठबंधन फ्यूल प्राइस को कम कर सकता है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे उम्मीद की जाने लगी कि सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत दे सकती है। मार्च 2024 से पेट्रोल और डीजल कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

अभी तक सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं मिली है। लेकिन, प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी CLSA सीएलएसए की मानें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 अक्टूबर के बाद कमी हो सकती है। सीएलएसए ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन की टिप्पणियों पर आधारित है। इसमें पिछले महीने कीमतों में कटौती का सुझाव दिया गया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जैन ने कहा था कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने पर विचार कर सकती हैं।

सीएलएसए ने अपने नोट में कहा, ₹महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य है। वहां के विधानसभा चुनाव,से पहले बीजेपी की अगुआई वाला गठबंधन लोकलुभावन कदम के रूप में ईंधन की कीमतों को कम करने पर विचार कर सकता है।₹

विधानसभा चुनाव की-फैक्टर

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र में नवंबर की शुरुआत में राज्य चुनाव होने की उम्मीद है। राज्य चुनाव की अंतिम तारीखों की घोषणा अक्टूबर के मध्य तक होने की संभावना है। सीएलएसए की रिपोर्ट बताती है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में किसी भी कटौती के साथ, सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ा सकती है।

अभी केंद्र पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 19.8 रुपये और 15.8 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगाता है। यह उत्पाद शुल्क 2021 के शिखर की तुलना में 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कम है। सीएलएसए के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में हर एक रुपये की बढ़ोतरी से सरकारी खातों में सालाना अतिरिक्त 16,500 रुपये और 5,600 करोड़ रुपये का संग्रह होगा।

उत्पाद शुल्क देश के भीतर वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर है। पेट्रोल और डीजल के मामले में उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा भारत के भीतर इन ईंधनों के उत्पादन या बिक्री पर लगाया जाने वाला टैक्स है।

क्रूड के भाव में भारी कमी

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। बुधवार को कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट ऑयल 74.15 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई 71.16 डॉलर प्रति बैरल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए सकारात्मक है।

हालांकि, संभावित दर कटौती और उत्पाद शुल्क वृद्धि से कंपनियों के झटका लग सकता है। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर थी।

एलआईसी और टाटा टेक से बड़ा आईपीओ लाएगी हुंडई, पैसे लगाने के लिए कब तक करना होगा इंतजार?

परिवहन विशेष न्यूज

Hyundai IPO 20 साल के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की ऑटो मेकर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। यह आईपीओ भारतीय बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ है। जी हां मारुति सुजुकी साल 2003 में अपना आईपीओ लाई थी इसके बाद अब हुंडई इंडिया अपना आईपीओ ला रही है। इस आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ (India's Largest IPO) की बात होती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और टाटा टेक्नॉलजी (Tata Technology) का नाम आता है। अब बाजार में जल्द ही ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी अपना सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है। जी हां, Hyundai की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर्स इंडिया अपना आईपीओ लाने के लिए तैयार है।

SEBI ने दी मंजूरी

हुंडई मोटर्स इंडिया ने हाल ही में ड्राफ्ट पेपर फाइल किया था। अब बाजार नियामक सेबी से कंपनी को मंजूरी मिल गई है। यानी आईपीओ लॉन्च होने का रास्ता साफ हो गया। कंपनी इस आईपीओ से 3 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है।

सबसे बड़ा आईपीओ

भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ की बात होती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम

यानी एलआईसी (LIC) का नाम आता है। एलआईसी ने साल 2022 में 2.7 अरब डॉलर का आईपीओ पेश किया था। अब एलआईसी को पीछे छोड़कर हुंडई मोटर्स आईपीओ (Hyundai Motors India IPO) अपना आईपीओ ला रहा है। सेबी से मंजूरी मिल जाने के बाद भी कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च की डेट नहीं बताई है। हालांकि, निवेशकों को उम्मीद है कि अक्तूबर में कंपनी का आईपीओ ओपन हो सकता है।

फ्रेश इश्यू नहीं लाएगा हुंडई

हुंडई मोटर्स इंडिया ने बताया कि वह इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू जारी नहीं करेगा। कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में बताया कि वह साउथ कोरियाई मूल की कंपनी में पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट में अपना ए हिस्सेदारी बेचेगी। इसका मतलब है कंपनी 'ऑफर फॉर सेल' जरिये रिटेल और अन्य निवेशकों को शेयर बेचेगी। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 14.2 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगा।

भारतीय शेयर बाजार में अपना आईपीओ लाने के बाद कंपनी का कैपिटलाइजेशन बढ़ सकता है। कंपनी जल्द ही अपने आईपीओ की डिटेल्स शेयर कर सकती है।

ऑटोमाबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ

Hyundai Motors India से पहले मारुति सुजूकी का आईपीओ आया था। मारुति सुजूकी ने साल 2003 में आईपीओ पेश किया था। इसका मतलब है कि लगभग 20 साल के बाद ऑटोमाबाइल सेक्टर में ऑटो मेकर कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार हुंडई का आईपीओ आने के बाद मार्केट

खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार; गेहूं-चावल से भरा देश का भंडार, दलहन-तिलहन में गिरावट

जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन रिकार्ड 13.78 करोड़ टन पर पहुंच गया जो 2022-23 में 13.57 करोड़ टन था। गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दलहन उत्पादन 2.60 करोड़ टन से घटकर 2.42 करोड़ टन और तिलहन उत्पादन 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया।

नई दिल्ली। भारत का खाद्यान्न उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन पर पहुंच गया है। गेहूं और चावल की बंपर फसल की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि फसल वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान इससे पिछले वर्ष के 32.96 करोड़ टन से 26.1 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है।

इस दौरान चावल उत्पादन रिकार्ड 13.78 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो 2022-23 में 13.57 करोड़ टन था। गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, दलहन उत्पादन 2.60 करोड़ टन से घटकर 2.42 करोड़ टन रह गया और तिलहन उत्पादन 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया।

मंत्रालय ने दालों, मोटे अनाजों, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट का कारण 'महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति' को बताया है। गन्ने का उत्पादन 49.05 करोड़ टन से घटकर 45.31 करोड़ टन रह गया, तथा कपास का उत्पादन 3.36 करोड़ गांठ से घटकर 3.25 करोड़ गांठ (एक गांठ 170 किलोग्राम) रह गया।

भारत में खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा और दालों को शामिल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि ये अनुमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं।

इस सीजन में धान की काफी अच्छी रोपाई हुई है। मानसून की बारिश ने इस बार धान की अच्छी रोपाई कराई है। सामान्य से अधिक बारिश एवं बुआई के रकबा से माना जा रहा है कि इस बार भी चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जा सकता है। भारत में 75 प्रतिशत धान का उत्पादन खरीफ मौसम (जून-सितंबर) में होता है।

मेक इन इंडिया ने किया कमाल; निर्यात बढ़ा, अर्थव्यवस्था भी हुई दमदार

मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सरकारी नोडल एजेंसी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के मुताबिक पिछले 10 सालों (2014-24) में 667.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हुआ जो उससे पूर्व के दस वर्षों (2004-14) की तुलना में 119 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात 400 अरब डॉलर के आंकड़े को पार किया।

नई दिल्ली। दस साल पहले वर्ष 2014 में मैन्युफैक्चरिंग व निवेश में बढ़ोतरी के साथ इनोवेशन और कौशल विकास जैसे चार उद्देश्यों के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह अपेक्षा के अनुरूप बढ़ा यह तो नहीं कहा जा सकता है, तेज गति की आवश्यकता बरकरार है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राह तैयार होने लगी है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सरकारी नोडल एजेंसी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के मुताबिक पिछले 10 सालों (2014-24) में 667.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ जो उससे पूर्व के दस वर्षों (2004-14) की तुलना में 119 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात 400 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार किया।

सेरामिक (Ceramic) व खिलौने जैसे क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हुई और हम आयातक से निर्यातक बन गए। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव रक्षा क्षेत्र में दिखा। कभी बुलेटप्रूफ जैकेट से लेकर जैकेट में इस्तेमाल होने वाले धागे के लिए आयात पर निर्भर देश अब रक्षा सेक्टर का निर्यातक बन गया।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम लाई गई और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर का प्रमुख निर्माता बन गया। एप्पल, फाक्सकान जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में निर्माण करने लगी तो चिप निर्माता अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भारत में यूनिट लगाने लगी।

तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ब्लाग में कहा कि 10 साल पहले देश में सिर्फ दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिसकी संख्या अब 200 से अधिक हो गई है। 10 साल पहले मोबाइल फोन निर्यात महज 1556 करोड़ रुपए का था जो अब 1.2 लाख करोड़ का हो गया। मतलब मोबाइल फोन के निर्यात में 7500 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अभी देश में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत निर्मित है। भारत मोबाइल निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में फिनिश्ड स्टील के निर्माण में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और भारत फिनिश्ड स्टील का बड़ा निर्यातक बन गया है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ के निवेश किए जा रहे हैं। पांच सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी दी गई है। 10 साल पहले 25 सितंबर को ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था।

डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने इस अवसर पर बताया कि अभी प्रतिवर्ष 60-70 अरब डॉलर का एफडीआई आ रहा है और आने वाले समय में हर साल 100 अरब डॉलर का एफडीआई आने की संभावना है। मेक इन इंडिया की मदद से अगले कुछ सालों में देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाने के लिए डीपीआईआईटी अब छोटे शहरों में औद्योगिक उत्पादन शुरू करवाने का प्रयास कर रहा हैउत्पादन की लागत को कम करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक सुविधा का विकास किया जा रहा है और राज्य अपनी-अपनी लॉजिस्टिक नीति भी बना रही है। 10 औद्योगिक शहरों की स्थापना की जा रही है जहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं पहले से उपलब्ध होंगी।

आधुनिक युग में लॉजिस्टिक्स उद्योग का इतिहास और इसकी महत्ता : डॉ. लॉजिस्टिक्स

लॉजिस्टिक्स उद्योग का इतिहास बेहद प्राचीन है और मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इसकी नींव पड़ी। प्रारंभिक युग में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए वस्तुओं के परिवहन और भंडारण की आवश्यकता पड़ी, और यहीं से लॉजिस्टिक्स का उदय हुआ। चाहे वह सिल्क रूट हो, समुद्री मार्गों से व्यापार हो, या औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे नेटवर्क का विस्तार—लॉजिस्टिक्स की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है।

लॉजिस्टिक्स का मूल उद्देश्य समय पर और उचित लागत पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। औद्योगिक क्रांति से पहले, यह केवल सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन जब विनिर्माण, उत्पादन और व्यापार के नए तरीके विकसित हुए, तब लॉजिस्टिक्स का महत्व और भी अधिक बढ़ गया।

आधुनिक युग में लॉजिस्टिक्स का विकास:

वर्तमान में, लॉजिस्टिक्स उद्योग ने अभूतपूर्व तकनीकी और प्रबंधन उन्नति देखी है। डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, और रोबोटिक्स ने लॉजिस्टिक्स की कार्यप्रणाली को अधिक सटीक, तेज़ और कुशल बना दिया है। आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ने कंपनियों को अपने उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं को स्वचालित और अनुकूलित करने में सक्षम किया है।

ई-कॉमर्स के उदय के साथ ही, लॉजिस्टिक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार, उत्पादों की शीघ्र और सुरक्षित डिलीवरी की आवश्यकता लॉजिस्टिक्स की अनिवार्यता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के जटिल नेटवर्क के कारण लॉजिस्टिक्स अब केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि किसी भी व्यापार का मूलभूत हिस्सा बन चुका है।

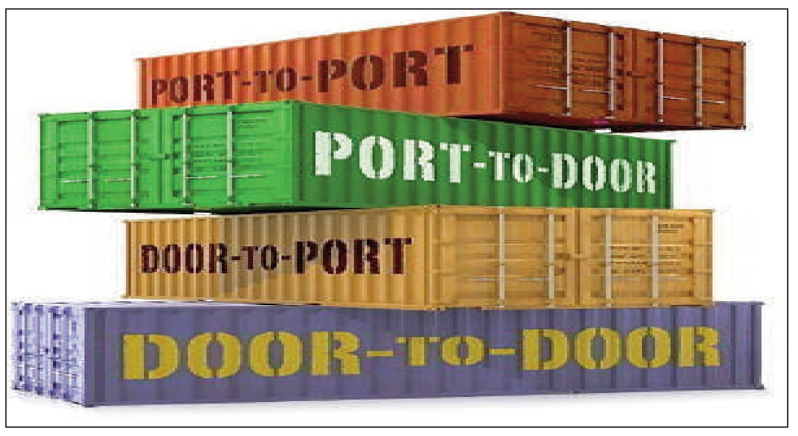

भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स का योगदान:

भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने के लिए लॉजिस्टिक्स उद्योग का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में कुशल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है। देश के हर कोने तक सही समय पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, निर्माण उद्योग हो, या ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स इन सभी के सुचारु संचालन के लिए अनिवार्य है।

सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार जैसे 'गति शक्ति योजना,' 'मेक इन इंडिया,' और 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं, और लॉजिस्टिक्स हब्स की स्थापना से लागत में कमी और समय की बचत हो रही है। इसका सीधा प्रभाव भारतीय निर्यात और आयात पर पड़ रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गति और भी तेज हो रही है।

वर्तमान ट्रेंड:

डिजिटलाइजेशन और तकनीकी अपग्रेडेशन: आधुनिक लॉजिस्टिक्स में डेटा-चालित निर्णय और ऑटोमेशन की भूमिका बहुत बढ़ गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों ने लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स: पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनियां अब हरित (ग्रीन) लॉजिस्टिक्स की दिशा में कार्य कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाले उपाय अब आवश्यक हो गए हैं।

ई-कॉमर्स और अंतिम-मील डिलीवरी: उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार के साथ अंतिम-मील डिलीवरी का महत्व बढ़ गया है। तेजी से डिलीवरी और बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनियां नई रणनीतियों का उपयोग कर रही हैं।

लॉजिस्टिक्स उद्योग आज भी किसी भी उद्योग और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चाहे वह विनिर्माण हो, कृषि हो, या सेवा उद्योग—लॉजिस्टिक्स के बिना कोई भी उद्योग सुचारु रूप से काम नहीं कर सकता। भारत जैसे देश में, जहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लॉजिस्टिक्स का सुधार और विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डॉ. लॉजिस्टिक्स एक पहल है जो पाठकों को लॉजिस्टिक्स उद्योग की गहरी समझ प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य है उद्योग के विभिन्न पहलुओं, कार्यों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना, ताकि लोग इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं और अवसरों को समझ सकें। यह पाठकों को लॉजिस्टिक्स के महत्व और इसकी जटिलताओं से अवगत कराकर उद्योग में उनकी समझ और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है।

डॉ. अंकुर शरण (डॉ. लॉजिस्टिक्स)
drlogistics.ankur@gmail.com

ऐसी रील किस काम की ?

हमारी अपनी पहचान विचारों से कार्यक्षमता व अपनी जिम्मेदारी से है ना कि झूठे दिखावे व फैशन से । आजकल नवयुवक युवतियों में रील का कल्चर आधुनिकता के कलेवर में ज्यादा हो गया है। नई पीढ़ी इस अंधी दौड़ या अंधकार से भरी खाईं में वह डुबती जा रही है। फैशन में नजरों की बात करने वालों को में एक बात कहना चाहता हूं कि भारत की परिकल्पना कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। सभ्यता समाज और उसकी परम्परा व संस्कृति सब की सब धूमिल हो चुकी है । लोग कहते हैं नजरिऐ को ठीक रखें अच्छा सोचें पर कैसे

जब ऐसे अमार्यादित कृत्य खुले आम बीच बाजार में झुठे दिखावे व चंद लाईक के चक्कर में युवती हमारे शहर की पहचान को खण्डित कर रही हो तो सम्भव नहीं है ? यह ठीक बात नहीं है फेमस होने के चक्कर में नई पीढ़ी भटकाव के रास्ते पर चल पड़ी है।

ऐसी रील किस काम की है जिसमें हमारी समाजिक संरचना सरोकार सब के सब बेबस व धूमिल हो रही हो । आज कल इन्दौर में महानगर का यह नाकारात्मक रंग अशोभनीय कृत्य सिर्फ झूठे दिखावे आधुनिकता की महानगरीय संस्कृति मानवीय सरोकार को मिटा रहीं हैं । ऐसी रील व विडियो शूट से युवती ने सारी हदें पार आम पब्लिक प्लेस में की जो भारतीय परम्परा के लिए दुखी करने वाली बात है। हिन्दु संगठन का बहुत बहुत साधुवाद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आवाज उन्होंने उठाई। हम सभी को इस प्रकार की रील व विडियो शूट करने वाली युवा पीढ़ी को समझने का प्रयास करना चाहिए । उनकी आधुनिक सोच में भारतीय संस्कृति व परम्परा का लेप लगाएं व सही गलत का मूल्यांकन उन्हें बताएं। कब तक वह रील के चक्कर में रीयल दुनिया से दूर रहेंगे। अश्लीलता के दामन से संस्कृति परम्परा का व समाजिक ताना-बाना का रंग दूषित होता जा रहा है । अर्थ नग्न फोटो शूट या वीडियो की रील बना कर वह भी सार्वजनिक स्थल पर ओर फिर उस विडियो को इंस्टाग्राम पर डाल कर पब्लिक रिएक्शन लिखा। अगर पब्लिक रिएक्शन बतातीं तो यह खुलें आम सिगरेट के धुंए शराब पी कर सड़कों पर हंगामा करते युवक युवती और यह अश्लीलता का यह नाकारात्मक पहलू के प्रति हम सभी जवाबदेही रखें । कहीं कुछ ग़लत हो रहा है तो विरोध करें अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वाले देशद्रोही है जो समाजिक मार्यदा व भारतीय संस्कृति को मिटा कर आधुनिकता का अंधेरा फैलाने की चेष्टा कर रहें हैं । शहर इन्दौर में नारीशक्ति पुण्य शाली लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की नगरी में इस प्रकार का कृत्य सहन नहीं किया जा सकता है। हमारी लोक माता अहिल्या बाई ने पूरी दुनिया में रीयल काम किए तभी तो इतने वर्षों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। रील बनने वाली युवती की आत्मा आधुनिकता की सारे हदें पार कर चुकी है। इसलिए समाज को आगे आ कर इन बहकाते हुए युवा कदमों को सही व सच्ची राह दिखाने हेतु उन्हें सकारात्मक प्रयासों से सही राह दिखाने का काम हम सभी को करना ही होगा। युवा पीढ़ी आधुनिकता के सागर में डूब रही है उसे बचाना हमारी समाजिक जिम्मेदारी है। सच के दर्पण से उनका मंथन करने हेतु सजगता व सही मार्गदर्शन जरूरी है तभी यह रीयल लाइफ रील के मोहपाश से दूर रहेंगी।

हरिहर सिंह चौहान
जबरी बाग़ नसिया इन्दौर मध्यप्रदेश 452001
मोबाइल 9826084157

पर्यावरण पाठशाला : फरीदाबाद के सेक्टर 31 स्थित टाउन पार्क की अनदेखी, पशुओं का मुक्त विचरण बना खतरा

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद के सेक्टर 31 में स्थित टाउन पार्क, जिसे कुछ साल पहले तक दशहरा ग्राउंड के रूप में जाना जाता था, अब शहर के दिल के रूप में उभर चुका है। इस पार्क ने अपनी विकास यात्रा में एक लंबा सफर तय किया है, जहाँ ज़मीन से शून्य पर शुरू होकर आज यह एक सुंदर और हरा-भरा पार्क बन चुका है। यह पार्क न केवल क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि पूरे शहर के पर्यावरणीय और सामाजिक ताने-बाने का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।

हालांकि, हाल के दिनों में पार्क को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या पार्क में आवारा पशुओं का मुक्त विचरण है। इन पशुओं की वजह से नए लगाए गए पौधे खतरे में हैं, क्योंकि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये पशु पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करेगी, बल्कि पार्क की खूबसूरती और हरियाली भी कम हो जाएगी।

स्वयंसेवकों द्वारा समय-समय पर इस मामले को उठाया गया है और संबंधित अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को इस समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह पार्क अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है।

यह समय है कि हम अपनी सोसाइटी और सार्वजनिक पार्कों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। पार्क में सुधार के लिए न केवल प्रशासनिक जागरूकता की आवश्यकता है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का भी योगदान जरूरी है। यदि हम अपने समाज के इस महत्वपूर्ण हिस्से की देखभाल नहीं करेंगे, तो यह प्राकृतिक संपदा धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगी।

सभी संबंधित अधिकारियों और नागरिकों से अपील है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और पार्क को सुरक्षित और हरा-भरा बनाए रखने में अपना योगदान दें।

संस्कारशाला: सोशल मीडिया की दोस्ती - आज की दुनिया में एक नया आयाम : अंकुर

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे अगर सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाए, तो जीवन में खुशियों की बारिश कभी खत्म नहीं होती। लेकिन, आज के समय में दोस्ती ने एक नया रूप धारण कर लिया है। सोशल मीडिया के युग ने दोस्ती को नए आयाम दिए हैं, जहाँ हर कोई हजारों 'दोस्तों' से घिरा हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में वह भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकता है।

पहले, दोस्ती की मिसाल दी जाती थी—₹प्राण जाए, पर वचन न जाए।₹ दोस्त के लिए हर हाल में खड़े रहने का वादा होता था। पर आज, सोशल मीडिया की दोस्ती में यह प्रतिबद्धता कहीं खो सी गई है। जब चाहे किसी को 'फ्रेंड' बना लिया और जब मन किया, 'ब्लॉक' कर दिया। यह एक तरह से दोस्ती का व्यापार सा हो गया है—मूल्यों और भावनाओं के बिना।

दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ में समय बिताना या बातें करना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझना और उन्हें हल करने में मदद करना है। लेकिन आज की दोस्ती में यह गहराई कम ही देखने को मिलती है। सोशल मीडिया ने हमें ऐसे दोस्त दिए हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, और शायद मिलना भी न हो, लेकिन इन आभासी रिश्तों ने हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका दिया है।

दोस्ती अब किसी संख्या का हिस्सा बन गई है—कितने 'फ्रेंड्स', कितने 'फॉलोअर्स'। लेकिन यह दोस्ती नहीं, एक छलावा है। वास्तविक दोस्ती का अर्थ है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो वह व्यक्ति हमारे साथ हो, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों न हो।

इसलिए, इस भीड़भाड़ में, जहां हर कोई खुद को सोशल मीडिया पर व्यस्त दिखाने में लगा है, दोस्ती का असली मतलब वही है जो हमें अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलता था—समय देना, साथ बिताना, और एक-दूसरे की परवाह करना। दोस्ती का असली खजाना यह नहीं है कि कितने लोग आपके साथ हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों के साथ सच्चाई से खड़े हैं।

अंत में, यह समझना जरूरी है कि दोस्ती से बढ़कर अगर कुछ है, तो वह है आपका अपना समय। अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए, इस आभासी दुनिया से थोड़ा दूर होकर, सच्चे रिश्तों में समय लगाएं।

सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

पाली: 68 वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता पाली के स्टेडियम में चल रही है धुरासनी स्कूल की चार टीमों के 22 छात्र व 22 छात्राएं भाग ले रही है आज चारों टीम के मैच हुए और चारों टीम जीती. 17 वर्ष छात्र टीम ने आउटरीच स्कूल पाली को हराया।17 वर्ष लड़कियों की टीम ने भांगेसर को हराया। 19 वर्ष छात्र टीम ने आर के स्कूल सोजत को हराया और 19 वर्ष लड़कियों की टीम ने पाली की सैन्ट्रल एकेडमी स्कूल को हराकर धुरासनी ने बाजी मारी। जिन जिन दानदाताओं ने सहयोग किया उनको खुशी होगी कि आपके दिया गया दान का बच्चे बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। खेल सामग्री अच्छी होने से बहुत फायदा मिला। टीम के मैनेजर कानाराम सीरवी ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। सीरवी ने कहा कि आगे भी भामाशाहो का इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। सभी टीमों के फाइनल में पहूंचने की शुभकामनाएं करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक आर्यवीर सिंह टांक उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ये जानकारी टीम के मैनेजर कानाराम सीरवी ने दी

'विकसित भारत 2047' और 'विकसित ओडिशा 2036' के लिए दिशानिर्देशों का सर्वेक्षण वेब पोर्टल पर किया जाएगा

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : 2047 भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी है। 2036 अलग ओडिशा राज्य के गठन की शताब्दी है। 'विकसित भारत 2047' और 'विकसित ओडिशा 2036' के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी। इसे गठित राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति की पहली बैठक समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन सभाकक्ष में आयोजित की गयी है।विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था, उद्योग और बुनियादी ढांचे, सामाजिक और मानव संसाधन विकास, संस्कृति और विरासत, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुशासन और ग्रामीण परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए एक सचिवालय समूह का गठन किया गया है।

मुख्य सचिव श्री आहूजा ने कहा, विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना हमारे लिए एक अनूठा अवसर लेकर आया है। उन्होंने इन दिशानिर्देशों को व्यवस्थित तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पर सभी संबंधित सचिवालय-स्तरीय क्षेत्रीय समूहों का सहयोग मांगा।विकास आयुक्त अनु गर्ग ने विभिन्न सचिवीय क्षेत्रीय समूहों की कार्य प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में भी जानकारी दी। उनका विचार था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। बैठक में गठित सचिवालय स्तर के क्षेत्रीय समूह और संचालन समिति के साथ नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, उद्योग में स्थापित नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से फीडबैक एकत्र करने के लिए जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया गया।

लक्ष्मी बस सेबा योजोना रोक गिया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़शिा

भुबनेस्वर् : दो-तीन माह से वेतन न मिलने पर चालक व स्टाफ बस के आगे बैठ रहे हैं। परिणामस्वरूप, भुवनेश्वर, ढेंकनाल जिले में ग्रामीण बस सेवा (लक्ष्मी) योजना को रोक दिया गया है। तत्कालीन नवीन सरकार ने प्रत्येक पंचायत से उपखंड कार्यालय तक लोगों की आनेजाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले फरवरी से यह लक्ष्मी बस सेवा प्रदान की है।भुवन ब्लॉक में कुल 7 बसें चल रही हैं। लोग काफी सुविधा के साथ आवागमन कर रहे हैं। लेकिन आज बस बंद होने से क्षेत्रवासियों को परेशान होते देखा जा रहा है। लेकिन, स्थानीय स्तर पर इसे समझने वाले पर्यवेक्षकों की मनमानी और धोखेबाज रवैये के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023